

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 20 मई, 2023 ई० (बैशाख 30, 1945 शक संवत्) [संख्या 20

विषय-सूची हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं. जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

	-141 1 1 1 1	,	ाजसस्य इस्मिन्स विस्तानिस्ता व्यापन		
विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक	विषय	पृष्ठ	वार्षिक
		चन्दा		संख्या	चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	_	रु0			रु0
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति,)	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	295—302		भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग १–क– नियम, कार्य-विधियां,			भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में		
आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,	l		प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा		> 1500			0.0
राजस्व परिषद् ने जारी किया	573-602		(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग १—ख (१) औद्योगिक न्यायाधिकरणों			भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट	_	١
के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय	J		सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी			भाग ७-क-उत्तर प्रदेशीय धारा समाओं के ऐक्ट		
किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ		
सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण		075	इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	70.00	
गजटा का उद्धरण		975		ر 79 ^{—96} ر	,
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई		
क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका			रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म- मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों		
परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत,			और मरने वालों के आँकड़े, फसल		
खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय)			और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	253-261	975
तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	211-230	975	स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र		1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह पुलिस विभाग (पुलिस सेवायें)

अनुभाग-2 25 मार्च, 2023 ई0 कार्यालय-ज्ञाप

सं0 517 / छ:पु0से0-2-23-522(87) / 2023—श्री वैभव कृष्ण, आईपीएस-आरआर-2010 के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 09 मार्च, 2023 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2023 से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100-2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से, संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव।

30 मार्च, 2023 ई0 पदोन्नत

सं0 543 / छःपु0से0-2-23-522(33) / 2022—भारतीय पुलिस सेवा (उ0 प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, विशेष पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु0-2,05,400-2,24,400) के निःसंवर्गीय अस्थायी पदों पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती—	
1	मनमोहन कुमार बशाल	आईपीएस-आरआर-1990
2	तनुजा श्रीवास्तव	आईपीएस-आरआर-1990
3	सतीश कुमार माथुर	आईपीएस-आरआर-1990
4	अंजु गुप्ता	आईपीएस-आरआर-1990
5	सुभाष चन्द्र	आईपीएस-आरआर-1990
6	प्रशान्त कुमार-I	आईपीएस-आरआर-1990

2—पुलिस महानिदेशक स्तर के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्ति उपलब्ध होने पर उपर्युक्त अधिकारियों के पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नित के उपरान्त विशेष पुलिस महानिदेशक का अस्थायी निःसंवर्गीय पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3—यह पदोन्नति / विज्ञप्ति आदेश, वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-E-12-876-X-2022-23, दिनांक 30 मार्च, 2023 में प्रदान की गई सहमति के क्रम में शासनादेश संख्या-542 / छःपु0से0-02-2023, दिनांक 30 मार्च, 2023 निर्गत होने के उपरान्त जारी किये जा रहे है।

सं0 544/छ:पु0से0-2-23-522(07)/2023—डॉ० देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ०प्र०, लखनऊ को शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या—21टी/छ:पु0से0-2-22-522(51)/2021, दिनांक 12 मई, 2022 द्वारा उनके पद के दायित्वों के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष), उ०प्र० का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के क्रम

में उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक के पदीय दायित्वों के निर्वहन किये जाने के फलस्वरूप श्री राज्यपाल द्वारा डाँ० देवेन्द्र सिंह चौहान, आईपीएस-आरआर-1988 को पे मैट्रिक्स लेवल-17 (रु० 2,25,000) अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> आज्ञा से, बी०डी० पाल्सन, सचिव।

31 मार्च, 2023 ई0 पदोन्नत

सं0 545 / छ:पु०से०-2-23-522(85) / 2022—भारतीय पुलिस सेवा (उ० प्र० संवर्ग) के अधिकारी श्री मनमोहन कुमार बशाल, आईपीएस-आरआर-1990 को दिनांक 01 अप्रैल, 2023 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु०-2,05,400-2,24,400) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2—श्री मनमोहन कुमार बशाल, आईपीएस-आरआर-1990 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 546 / छ:पु०से०-2-23-522(84) / 2022—भारतीय पुलिस सेवा (उ० प्र० संवर्ग) के अधिकारी श्री बी०डी० पाल्सन, आईपीएस-आरआर-1998 को दिनांक 01 अप्रैल, 2023 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु०-1,82,200-2,24,100) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2—वर्ष-1998 बैच के शेष अधिकारियों की पदोन्नित के आदेश रिक्तियां उपलब्ध होने पर यथासमय पृथक से निर्गत किये जायेगें।

3—श्री बी०डी० पाल्सन, आईपीएस-आरआर-1998 की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत्त किये जायेंगे।

> आज्ञा से, ए०वी० राजामौलि, सचिव।

अनुभाग-1 05 अप्रैल, 2023 ई0 प्रोन्नति

संव 537 / छःपु०से०-1-2023-डी०पी०सी०(सी०एल०-02) / 2021—चयन वर्ष 2022—2023 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल—13, रु० 1,23,100-2,15,900) में उपलब्ध / सम्भावित रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी, 2023 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तदसमय पात्रता सूची में श्री अजीजुल हक (ज्येष्ठता क्रमांक-216) का नाम क्रमांक-21 पर सम्मिलित था। श्री अजीजुल हक के विरूद्ध थाना-कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-637 / 07 धारा-419, 420, 467, 468, 469 471, 120बी० 34 भा०द०वि० व धारा-07 / 12 / 13 भ्र०नि०अधि० मा० पी०सी० कोर्ट गोरखपुर के न्यायालय में उक्त वाद विचाराधीन होने के दृष्टिगत समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री अजीजुल हक का चयन 01 पद सुरक्षित रखते हुए 'आस्थिगित' रखे जाने की संस्तुति की गयी।

2—अपर जनपद न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि०अधि०) कोर्ट संख्या-०५ गोरखपुर के आदेश दिनांकित 19 जनवरी, 2023 द्वारा अपराध का होना प्रमाणित न पाये जाने पर श्री अजीजुल हक, अपर पुलिस आधीक्षक के विरुद्ध दाखिल अन्तिम रिपोर्ट संख्या-02 / 2018 दिनांक 17 नवम्बर, 2018 मु0अ०सं०-637 / 07 धारा—419, 420, 467, 468, 469, 471, 120बी0, 34 भा0द0वि0 व धारा-07/12/13 भ्र0नि0अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा मा0 न्यायालय सीजेएम, जनपद गोण्डा स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप श्री अजीजुल हक को उक्त वेतनमान में प्रोन्नित होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की दिनांक 15 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अजीजुल हक (ज्येष्ठता क्रमांक—216) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी—दो (वेतनमान 37,400-67,000 ग्रेड-पे रु० 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु० 1,23,100-2,15,900) में उनके किनष्ठ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-217) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नित होने की तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2023 से नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री अजीजुल हक (ज्येष्ठता क्रमांक-216) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु० 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु० 1,23,100-2,15,900) में उनके किनष्ठ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-217) को उक्त (वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2023 से नोशनल प्रोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

सं० 538 / छ:पु०से०-1-2023—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड—पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उपलब्ध / सम्भावित रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तदसमय पात्रता सूची में श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर (ज्येष्ठता क्रमांक-344) का नाम क्रमांक-08 पर सम्मिलित था। श्री राठौर के विरुद्ध शासन द्वारा पारित परिनिन्दा आदेश दिनांकित 05 जुलाई, 2021 के दृष्टिगत समिति द्वारा अनुपयुक्त पाते हुए उनके नाम की संस्तुति नहीं की गयी।

2—श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर के विरूद्ध 'परिनिन्दा' दण्ड को शासन के आदेश संख्या-927 / छःपु०से०-1-2022-रिट-26 / 2021 दिनांक 27 जून, 2022 द्वारा समाप्त किया गया।

3—चयन वर्ष 2022-2023 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेंड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उपलब्ध / सम्भावित रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी, 2023 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध निर्गत कारण बताओं नोटिस के दृष्टिगत समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर का चयन 01 पद सुरक्षित रखते हुए 'अस्थिगत' रखे जाने की संस्तुति की गयी।

श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर, पुलिस उपाधीक्षक के विरूद्ध निर्गत कारण बताओं नोटिस को शासन के कार्यालय आदेश संख्या-343 / छःपु०से०-1-2023-01(अनु०) 2021 दिनांक 25 फरवरी, 2023 द्वारा इन्हें भविष्य के लिए कठोर चेतावनी प्रदान करते हुए प्रकरण को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर को उक्त वेतनमान में प्रोन्नित होने की तिथि से नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की दिनांक 15 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर को (ज्येष्ठता क्रमांक-344) को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल—12, रु० 78,800-2,09,200) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तत्काल प्रभाव से वास्तविक पदोन्नित प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

4—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर को (ज्येष्ठता क्रमांक-344) को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) को उक्त वेतनमान में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

सं० 539 / छ:पु०से०-1-2023—चयन वर्ष 2022—2023 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उपलब्ध / सम्भावित रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी, 2023 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तदसमय पात्रता सूची में श्री पवन गौतम (ज्येष्ठता क्रमांक-430) का नाम क्रमांक-30 पर सम्मिलित था। श्री पवन गौतम के विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस के दृष्टिगत समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री पवन गौतम का चयन 01 पद सुरक्षित रखते हुए 'आस्थिगत' रखे जाने की संस्तुति की गयी।

2—श्री पवन गौतम, पुलिस उपाधीक्षक के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस को शासन के कार्यालय आदेश संख्या—103 / छ:पु०से०-1-2023-22(विविध)2022 दिनांक 01 फरवरी, 2023 द्वारा इन्हें भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप श्री पवन गौतम (ज्येष्ठता क्रमांक-430) को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उनके किनष्ठ श्री अखण्ड प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-431) के उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2023 से नोशनल प्रोन्नित पर विचार किये जाने का प्रस्ताव विभागीय चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विभागीय चयन समिति की दिनांक 15 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री पवन गौतम (ज्येष्ठता क्रमांक-430 को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उनके किनष्ठ श्री अखण्ड प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-431) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2023 से नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

3—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री पवन गौतम (ज्येष्ठता क्रमांक-430) को अपर पुलिस अधीक्षक (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पेलेवल-12, रु० 78,800-2,09,200) में उनके किनष्ठ श्री अखण्ड प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-431) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2023 से नोशनल प्रोन्नित तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 540 / छःपु०से०-1-2023-पी०एफ०-02 / 2022—चयन वर्ष 2020-2021 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु० 67,700-2,08,700) में उपलब्ध / सम्भावित रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में तदसमय पात्रता सूची में श्री नितेश प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-652) का नाम क्रमांक-28 पर सिम्मिलित था। श्री नितेश प्रताप सिंह के विरुद्ध प्रचितत अनुशासनिक कार्यवाही के दृष्टिगत समिति द्वारा तद्समय सम्यक् विचारोपरान्त श्री नितेश प्रताप सिंह का चयन 01 पद सुरक्षित रखते हुए 'आस्थिगत' रखे जाने की संस्तुति की गयी।

2—श्री नितेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही को शासन के कार्यालय आदेश संख्या—661 / छ:पु०से०-1-2022-23(अनु०) / 2020टीसी दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा परिनिन्दा का दण्ड प्रदान करते हुए समाप्त की गयी। उक्त परिनिन्दा के दण्ड को शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1860 / छ:पु०से०-1-2022-23(अनु०) / 2020टीसी दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 द्वारा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप चयन वर्ष 2022-23 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नित के संबंध में दिनांक 10 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गयी संस्तुति के अनुसार श्री नितेश प्रताप सिंह को दिनांक 13 जनवरी, 2023 को पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु० 67,700-2,08,700) के पद पर प्रोन्नित प्रदान की गयी है।

3—श्री नितेश प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक—652) को पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु० 67,700-2,08,700) में उनके किनष्ठ श्री अशोक कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-654) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से नोशनल प्रोन्नित पर विचार किये जाने का प्रस्ताव चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2023 में चयन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री नितेश प्रताप सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-652) को पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु० 67,700-2,08,700) में उनके किनष्ठ श्री अशोक कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-654) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

4—अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री नितेश प्रताप सिंह. (ज्येष्ठता क्रमांक-652) को पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान (वेतनमान 15,600-39,100 ग्रेड-पे रु० 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु० 67,700-2,08,700) में उनके कनिष्ठ श्री अशोक कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-654) को उक्त वेतनमान में प्रोन्नत होने की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

आज्ञा से, संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव।

अनुभाग—2 05 अप्रैल, 2023 ई0 पदोन्नति

सं0 573 / छ:पु0से0-2-23-522(84) / 2022—भारतीय पुलिस सेवा (उ0 प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु0-1,82,200-2,24,100) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	सर्वश्री / श्रीमती—	
1	के0 सत्यनारायन	आईपीएस-आरआर-1998
2	पदमजा चौहान	आईपीएस-आरआर-1998

2-उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेगें।

आज्ञा से, ए०वी० राजामौलि, सचिव।

अनुभाग-1 13 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 503 / छ:-पु0से0-1-2023-02(अधियाचन) / 2023—चयन वर्ष 2020-2021 में पुलिस उपाधीक्षक (प्रोन्नित कोटे) में निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नित हेतु कुल 102 रिक्तियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में दिनांक 18 फरवरी, 2021 को विभागीय चयन समिति की आहूत बैठक में श्री सतीश यादव, पीएनओ-042330093 (संयुक्त वरिष्ठता सूची के क्रमांक 06 व पात्रता सूची के क्रमांक-06) को प्रोन्नित प्रदान की गयी। तत्समय उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा श्री सतीश यादव पीएनओ-042330093 के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य की सूचना नहीं दी गयी, जिसके कारण विभागीय चयन समिति की बैठक में

इनके प्रोन्नित हेतु संस्तुति प्रदान की गयी। उ०प्र० लोक सेवा आयोग में हुई बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2021 को विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के आदेश संख्या 02/2021/आई/55681/2021 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा श्री सतीश यादव को प्रोन्नित प्रदान की गयी।

2—अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो/ब-61ए/2020-21 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 द्वारा अवगत कराया गया कि विष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के आदेश संख्या द-134/2020 दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 द्वारा श्री सतीश यादव को पिरनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया, किन्तु उक्त दण्डादेश दिनांकित 31 अक्टूबर, 2020 का अंकन श्री सतीश यादव उपरोक्त के सेवाभिलेखों में न होने के कारण श्री यादव की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नित की गयी। अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में शासन के पत्र संख्या 4061/छ:पु०से०-1-2022 दिनांक 06 जनवरी, 2023 द्वारा श्री सतीश यादव पीएनओ-042330093 सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक के प्रोन्नित निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से अनुरोध किये जाने के साथ ही विषयगत प्रकरण में दोषी कार्मिकों को दिण्डत करते हुए उसकी आख्या तत्काल शासन एवं उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन को निर्देशित किया गया।

3—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-दो / ब-61ए / 2020-21 दिनांक 13 मार्च, 2023 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सतीश यादव, पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस को प्रदत्त दण्डादेश संख्या-द-134 / 2020 दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को इनके सेवाभिलेखों में अंकन न किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्मिक श्री रनवीर यादव, पुलिस उ०िन० (लिपिक) जनपद मैनपुरी को पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के आदेश संख्या-द-989 / 2022 दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधीकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के उपरान्त '"परिनिन्दा लेख" का दण्ड प्रदान किया गया है इसके अतिरिक्त श्री रामनरेश अग्निहोत्री, सहायक पुलिस उ०िन० (लिपिक) जनपद मैनपुरी सम्प्रति सी०बी०सी०आई०डी० मुख्यालय लखनऊ को पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के आदेश संख्या-द-989 / 2022 दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही में "परिनिन्दा लेख" एवं वर्ष 2021 की "सत्यनिष्ठा" रोके जाने का दण्डादेश पारित किया गया है।

4—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-361/10/पी0/सेवा-1/2020-2021 दिनांक 24 मार्च, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयन वर्ष 2020-21 में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2021 द्वारा प्रान्तीय पुलिस सेवा के पदोन्नित कोटे में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर श्री सतीश यादव, ज्येष्ठता क्रमांक-6 व संस्तुत सूची के क्रमांक-5 को प्रोन्नित हेतु प्रदान की गयी संस्तुति निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 मार्च, 2023 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सतीश यादव ज्येष्ठता क्रमांक-6 की पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गयी पदोन्नित परिनिन्दा दण्ड के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासन के आदेश संख्या-02/2021/आई/55681/2021 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा श्री सतीश यादव, ज्येष्ठता क्रमांक-6 की पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गयी प्रोन्नित को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

20 अप्रैल, 2023 ई0

प्रोन्नति

सं0 780 / छ:-पु0से0-1-2023-डी.पी.सी.(सी0एल0-01) / 2021—उत्तर प्रदेश, प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी—दो (वेतनमान 37,400—67,000, ग्रेड—पे रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पेलेवल-13, रु० 1,23,00-2,15,900) में कार्यरत अधिकारियों की अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु० 8900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पेलेवल-13क, रु० 1,31,100-2,16,600) में प्रोन्नत किये जाने के

संबंध में विभागीय चयन समिति, की सम्पन्न बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2023 में कुँवर ज्ञानन्जय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो के विरूद्ध तत्समय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उनके संबंध में विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहरबंद लिफाफे में रखी गयी।

2—कुँवर ज्ञानन्जय सिंह के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-344/छ:पुसे0-1-2023-01(अनु0)/2021 दिनांक 25 फरवरी, 2023 द्वारा 'कठोर चेतावनी' प्रदान करते हुए समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/2021/89-क-1997 दिनांक 28 मई, 1997 के नियम-7 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय चयन समिति की मुहरबंद लिफाफे में रखी गयी संस्तुति का अनावरण किया गया।

3—मुहरबंद लिफाफे में की गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में (कुँवर ज्ञानन्जय सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-2 (ज्येष्ठता क्रमांक-155) को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु० 8900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13-क, रु० 1,31,100-2,16,600) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नित किये जाने एवं इनके सन्निकट किनष्ट श्री राम नयन सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-156) की इस वेतनमान में प्रोन्नित तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2023 से नोशनल प्रोन्नित प्रदान किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

4—कुँवर ज्ञानन्जय सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो की अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-एक में प्रोन्नित के फलस्वरूप तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

> आज्ञा से, संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 मई, 2023 ई० (बैशाख 30, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD [ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

January 23, 2023

No. 89–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 19-01-2023, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad/Lucknow Bench are hereby confirmed on their post from the date mentioned against their names:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
		(S/Sri)–	
1	2892	Chhote Lal-II, Lko.	12-11-2020
2	9189	Samyadeep Ganguly	18-11-2020
3	7132	Shyam Sundar Prasad	22-03-2022
4	7285	Arvind Kumar Shashank, Lko.	28-07-2021
5	7335	Abhishek Srivastava	01-06-2021
6	7348	Smt. Prachi Pandey, Lko.	26-06-2021
7	6053	Dinesh Kumar	16-09-2021
8	7349	Bhupendra Singh	17-09-2021
9	7350	Pannu Yadav, Lko.	16-09-2021
10	7351	Saurabh Srivastav, Lko.	16-09-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
11	7352	Mohd. Shoeb, Lko.	24-09-2021
12	7353	Onkar Srivastava	16-09-2021
13	7354	Smt. Ranjana	16-09-2021
14	7355	Ambrish Pandey, Lko.	16-09-2021
15	7356	Komal Chandra	16-09-2021
16	7358	Durgesh Kumar Singh	16-09-2021
17	7361	Chandresh Kumar Vishwakarma	16-09-2021
18	7362	Omendra Pratap Singh Chauhan, Lko.	16-09-2021
19	7363	Sunil Kumar, Lko.	16-09-2021
20	7364	Mrs. Tripti Shikhar Srivastava, Lko.	05-10-2021
21	7365	Mrs. Priyanka Bajpai, Lko.	17-09-2021
22	7366	Arunabh Sharma	16-09-2021
23	7368	Shikhar Srivastava, Lko.	16-09-2021
24	7369	Chanda Pandey	16-09-2021
25	7371	Enab Jaffrey, Lko.	17-09-2021
26	7372	Ms. Shipra Gupta, Lko.	16-09-2021
27	7373	Ms. Varsha Tripathi, Lko.	17-09-2021
28	7375	Sunil Kumar Rai	01-10-2021
29	7377	Devendra Tripathi	01-10-2021
30	7378	Sudhansu Mishra, Lko.	03-10-2021
31	7379	Rajiv Kumar	03-11-2021
32	7380	Saurabh Sinha	18-11-2021
33	7383	Ashutosh Shukla	18-11-2021
34	7385	Vaibhav Tripathi, Lko.	09-12-2021
35	7387	Ashutosh Singh	16-12-2021
36	7388	Smt. Vibhuti Singh	01-01-2022
37	7389	Anjali Malviya	01-01-2022
38	7391	Rakesh Kumar	04-01-2022
39	7392	Smt. Abhilasha Gupta, Lko.	13-01-2022
40	7393	Sanjay Kumar Srivastava	02-02-2022
41	7394	Pawan Kumar Singh	01-02-2022
42	7395	Ms. P.V. Chandrakala	01-03-2022
43	7396	Anil Kumar Sharma, Lko.	01-02-2022
44	7397	Mrs. Rashmi Yadav, Lko.	04-03-2022

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

No. 90–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 19-01-2023, following Review Officers, High Court, Allahabad/Lucknow Bench are hereby confirmed on their post from the date mentioned against their names :

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of confirmation
1	2	3	4
		(S/Sri)–	
1	10730	Smt. Namita Srivastava	28-10-2021
2	10731	Smt. Poonam Kanaujia	27-10-2021
3	10801	Ms. Deeksha Gupta, Lko.	31-10-2021
4	10820	Ajeet Singh Kushawaha	05-11-2021
5	10821	Chandra Shekhar Dwivedi, Lko.	31-10-2021
6	10822	Deepak Singh	30-10-2021
7	10823	Shiv Raj Singh	27-10-2021
8	10824	Shani Yadav	31-10-2021
9	10825	Vivek Dwivedi	02-11-2021
10	10826	Devendra Singh	02-11-2021
11	10827	Vimaldeep Singh	03-11-2021
12	10828	Apoory Srivastava	29-10-2021
13	10829	Prakhar Singh	31-10-2021
14	10830	Deepak Kumar Singh	27-10-2021
15	10831	Rajan Gupta	02-11-2021
16	10832	Ms. Shalini Singh	31-10-2021
17	10833	Kushmakar Shukla, Lko.	31-10-2021
18	11033	Jaivardhan	29-10-2021
19	11034	Sushil Kumar Tiwari	31-10-2021
20	11035	Vaibhav Srivastava	02-11-2021
21	11036	Shivam Tiwari (Relieved w.e.f. 17-01-2022)	07-11-2021
22	10835	Anurag Verma	29-10-2021
23	11037	Shivendra Bisht	02-11-2021
24	10836	Ms. Abhilasha Katiyar	02-11-2021
25	10837	Akash Shukla	02-11-2021
26	10838	Ms. Shreya Awasthi	02-11-2021
27	10839	Kanishk Rai	31-10-2021
28	10840	Avinash Chaudhary, Lko.	02-11-2021
29	10843	Ms. Divya Jain	31-10-2021
30	11038	Saurabh Kumar Singh	27-10-2021
31	10844	Shivam Gupta	02-11-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
32	11039	Rajat Kumar Singh	02-11-2021
33	10845	Kapil Dev Tripathi	30-10-2021
34	10846	Jyoti Shanker Gupta	02-11-2021
35	10847	Abhishek Tripathi	27-10-2021
36	10848	Vaibhav Chaudhri	31-10-2021
37	10849	Praveen Kumar	28-10-2021
38	11040	Nrependra Dimree	02-11-2021
39	10851	Kamendra Kumar	31-10-2021
40	10852	Arvind Kumar	31-10-2021
41	10853	Suyash Goswami	27-10-2021
42	10854	Amit Kumar Pandey	02-11-2021
43	10855	Pradeep Kumar Tripathi	03-11-2021
44	10856	Kripa Shankar Goswami	31-10-2021
45	10857	Mayank Katiyar	02-11-2021
46	10859	Mohd. Shahnawaz	31-10-2021
47	10860	Gyanendra Kumar	31-10-2021
48	10861	Prakhar Katiyar	31-10-2021
49	10862	Krishna Kumar	02-11-2021
50	11041	Ashish Kumar Singh	02-11-2021
51	10863	Ayush Shukla	31-10-2021
52	11078	Prawal Pandey	02-11-2021
53	11079	Shreyas Singh	03-11-2021
54	11042	Shivam Dubey	27-10-2021
55	10865	Alok Patel	31-10-2021
56	10867	Abhay Pathak	28-10-2021
57	11085	Sunil Kumar Bharti	02-11-2021
58	11043	Adbhut Mishra	31-10-2021
59	10868	Vipin Yadav	29-10-2021
60	10869	Amit Kumar	31-10-2021
61	11044	Harsh Vardhan Chaturvedi	02-11-2021
62	10870	Amit Kumar Yadav	02-11-2021
63	10871	Ms. Asma Khan	03-11-2021
64	10872	Achyut Shukla (Relieved w.e.f. 20-05-2022)	02-11-2021
65	11045	Saurabh Pal	02-11-2021
66	10873	Ankur Singh	31-10-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
67	10874	Abhishek Singh	07-11-2021
68	10875	Ashok Kumar Singh	28-10-2021
69	10876	Deepak Raj	27-10-2021
70	10877	Vaibhav Kumar Chaturvedi	02-11-2021
71	10878	Saurabh Sahu	31-10-2021
72	10879	Alok Kumar Pandey	28-10-2021
73	10880	Anoop Kumar Shukla	31-10-2021
74	10881	Ashish Kumar	02-11-2021
75	10882	Prabhat Kushwaha	30-10-2021
76	10883	Shashank Mishra	02-11-2021
77	10884	Nishant Pachouri (Relieved w.e.f. 25-02-2022)	28-10-2021
78	10885	Gaurav Shrivastav	02-11-2021
79	10887	Vivek Kumar Sharma	02-11-2021
80	10888	Amit Kumar Singh	31-10-2021
81	10889	Abhishek Singh	02-11-2021
82	10890	Ashwani Kumar	02-11-2021
83	10891	Akarsh Khare	02-11-2021
84	10892	Ankit Bajpai	28-10-2021
85	11046	Ms. Rishi Kanaujia	28-10-2021
86	10893	Divyanshu Gupta, Lko.	02-11-2021
87	11080	Deependra Singh Chauhan	02-11-2021
88	10896	Girindra Sir Dubey	29-10-2021
89	11047	Prakash Bansal (Relieved w.e.f. 23-08-2022	03-04-2022
90	10897	Amar Kumar Sharma	29-10-2021
91	10899	Ms. Shaziya Fatima	28-10-2021
92	10900	Ms. Aditi Srivastava, <i>Lko</i> .	31-10-2021
93	10902	Ashish Kumar Kushwaha	02-11-2021
94	10904	Ms. Swati Sachan	02-11-2021
95	10905	Ms. Shaumya	02-11-2021
96	10907	Abdul Lateef	27-10-2021
97	10908	Arvind Pratap Singh	02-11-2021
98	10909	Surendra Singh	31-10-2021
99	11048	S Anand	29-10-2021
100	10910	Ashwani Batham	02-11-2021
101	11083	Ms. Parul Tripathi	31-10-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
102	10911	Dinesh Kumar Pal	28-10-2021
103	10912	Abhishek Yadav	02-11-2021
104	10913	Ashwani Yadav	31-10-2021
105	10914	Anshul Verma	02-11-2021
106	10915	Kishan Kumar Jaiswal	02-11-2021
107	11049	Ms. Shalinee Sengar	01-12-2021
108	10916	Ms. Swati Devi	31-10-2021
109	10917	Ajay Kumar Maurya	28-10-2021
110	10918	Abhishek Kumar Gautam	02-11-2021
111	10919	Ms. Komal Dogra	29-10-2021
112	11050	Ajeet Kumar Singh	02-11-2021
113	10920	Prashant Kumar Goswami	02-11-2021
114	10921	Rajesh Kumar	02-11-2021
115	10923	Birjoo Yadav	31-10-2021
116	10924	Mahendra Kumar Maurya	31-10-2021
117	10925	Mayank Singh	27-10-2021
118	10926	Himanshu Kumar	02-11-2021
119	10927	Ankit Kumar Verma	02-11-2021
120	10928	Ms. Suman	02-11-2021
121	10929	Ms. Priya Kesarwani	27-10-2021
122	10930	Ms. Shikha Tiwari	31-10-2021
123	11052	Ms. Shaivee Srivastava	02-11-2021
124	10931	Ms. Aakriti Mishra	31-10-2021
125	11086	Pavan Pratap Yadav	02-11-2021
126	10932	Ms. Kumari Roopshri Singh	31-10-2021
127	10933	Ms. Saroja Mourya, Lko.	02-11-2021
128	11081	Ms. Akshima Srivastava	02-11-2021
129	10934	Awanish Kumar Gupta	29-10-2021
130	11075	Atul Verma	31-10-2021
131	10935	Piyush Kumar	30-10-2021
132	10936	Avdhesh Kumar Verma	30-10-2021
133	10937	Satyendra Kumar Jha	02-11-2021
134	10938	Kaushlendra Verma	31-10-2021
135	10939	Aman Verma	31-10-2021
136	10940	Nishikant Verma	31-10-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
137	11054	Arun Kumar Yadav	28-10-2021
138	10941	Kuldeep Yadav	30-10-2021
139	10942	Ram Swaroop Sahu	28-10-2021
140	10943	Gupta Ravi Jaiprakash	02-11-2021
141	10944	Ms. Shahnila Khaliq	03-11-2021
142	10945	Ms. Unique Gangwar, Lko.	25-02-2022
143	10946	Anshuman	28-10-2021
144	10947	Ms. Shivani Tomar, Lko.	02-11-2021
145	11055	Pankaj Kumar Yadav	02-11-2021
146	10949	Pushpendra Malik	02-11-2021
147	10950	Vijay Kumar	28-10-2021
148	10951	Ms. Deepika Rai	02-11-2021
149	10952	Ms. Bushra Rehman	27-10-2021
150	10953	Anoop Singh	31-10-2021
151	11056	Mayank Yadav, Lko.	31-10-2021
152	10954	Ms. Poornima Mishra	17-11-2021
153	10955	Mukund Bhaskar	31-10-2021
154	10956	Ms. Neeti Chauhan	28-10-2021
155	10957	Satyendra Kumar	02-11-2021
156	10958	Ravi Prakash	02-11-2021
157	11058	Pushpendra Singh Niranjan	02-11-2021
158	10959	Ms. Chhaya Singh	31-10-2021
159	11059	Ms. Yashika Gupta	27-10-2021
160	10960	Ms. Sudha	28-10-2021
161	11060	Alok Kumar	31-10-2021
162	10961	Rohit Nandan	31-10-2021
163	10962	Ms. Ankita Tiwari	27-10-2021
164	10963	Gopal Sharma	02-11-2021
165	10964	Abhinay Kumar, Lko.	02-11-2021
166	10965	Avneesh Kumar	04-11-2021
167	10966	Arvind Kumar Yadav	28-10-2021
168	10967	Satendra Kumar	03-11-2021
169	10968	Nidhish Singh	02-11-2021
170	10969	Ms. Shweta Singh	27-10-2021
171	10970	Arun Kumar	02-11-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
172	10971	Ms. Sankalp Singh	29-10-2021
173	10972	Ashutosh Kumar Sonker	02-11-2021
174	10973	Ms. Sonam Verma	31-10-2021
175	10974	Ms. Richa Verma, Lko.	02-11-2021
176	10975	Siddharth Jain	27-10-2021
177	10976	Ms. Surmila Pal	31-10-2021
178	10977	Ms. Tripti Verma	02-11-2021
179	10978	Ms. Priyanka	02-11-2021
180	10979	Ms. Priyanka Chaurasia	02-11-2021
181	10980	Piyush Kapil	31-10-2021
182	10981	Atul Sharma	30-10-2021
183	10982	Ms. Rachna Singh	03-11-2021
184	10983	Ms. Jyoti Kushwaha	27-10-2021
185	10984	Gorakh Nath	02-11-2021
186	11061	Ms. Reena Chauhan	02-11-2021
187	11062	Vishal Verma	02-11-2021
188	11063	Arvind Maurya	31.10-2021
189	10987	Ram Manoj	02-11-2021
190	10988	Fanendra Pal Singh	30-10-2021
191	11065	Roshan Kumar	29-10-2021
192	10990	Prabhat Kumar Singh	31-10-2021
193	10991	Rupesh Gautam	29-10-2021
194	10992	Kunal Raj	02-11-2021
195	10994	Maninder Sahai	31-10-2021
196	10995	Priyanshu Sagar	02-11-2021
197	10996	Ms. Maneesha Gautam	02-11-2021
198	10997	Pradip Kumar Saroj	31-10-2021
199	10998	Ms. Priyanka Gautam	02-11-2021
200	10999	Arjun Kumar Kanaujiya	31-10-2021
201	11000	Anuj Kumar	02-11-2021
202	11001	Mayank Bishwari	02-11-2021
203	11002	Gaurav Rawat	02-11-2021
204	11003	Balvendra Kumar Rawat	05-11-2021
205	11004	Suresh Kumar Singh	31-10-2021
206	11005	Ms. Chitralekha	27-10-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
207	11066	Akash Gaurav	02-11-2021
208	11006	Nitish Kumar Ojha	03-11-2021
209	11007	Mrs. Rekha	28-10-2021
210	11008	Alok Kumar	02-11-2021
211	11069	Abhishek Kumar, Lko.	02-11-2021
212	11009	Ashok Kumar Verma	30-10-2021
213	11010	Siddhant Kumar	31-10-2021
214	11011	Vijay Kumar	02-11-2021
215	11012	Akshay Singh	02-11-2021
216	11013	Himanshu Angolkar	02-11-2021
217	11014	Pankaj Kumar	27-10-2021
218	11070	Anil Kumar	31-10-2021
219	11015	Siddharth Saroj	27-10-2021
220	11016	Km. Asha	02-11-2021
221	11017	Rajesh Kumar Gond	02-11-2021
222	11018	Jitendra Kumar	27-10-2021
223	11019	Jaiveer Singh	30-10-2021
224	11020	Satyendra Kumar Mishra	28-10-2021
225	11021	Manoj Kumar	02-11-2021
226	11022	Avnish Kumar Verma	30-10-2021
227	11023	Neeraj Kumar	02-11-2021
228	11024	Laldeo Patel	29-10-2021
229	11025	Raj Kumar	31-10-2021
230	11026	Saurabh Shukla	31-10-2021
231	11027	Dheerendra Kumar Pandey	31-10-2021
232	11028	Pankaj Singh	27-10-2021
233	11029	Tej Bahadur	27-10-2021
234	11073	Kandarp Mishra	27-10-2021
235	11030	Smt. Shashi Kanta Chaudhary, Lko.	28-10-2021
236	11074	Rahul Kumar	31-10-2021
237	11031	Dhirendra Pratap	02-11-2021
238	11130	Ram Pratap Singh	23-11-2021
239	11132	Pramod Kumar	20-11-2021
240	11133	Sandhya Tripathi	17-11-2021
241	11134	Pushkar Mishra, Lko.	18-11-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
242	11135	Rajesh Singh	17-11-2021
243	11136	Vikash Gaurav	24-11-2021
244	11138	Apoorva Singh	19-11-2021
245	11139	Shivam Singh	18-11-2021
246	11140	Neeraj Singh Patel	21-11-2021
247	11141	Rohit Kumar Verma	23-11-2021
248	11142	Ram Babu	18-11-2021
249	11144	Hari Bhagwan Kushwah	23-11-2021
250	11251	Gaurav Tiwari	14-12-2021
251	11145	Pavan Kumar	23-11-2021
252	11146	Rabindra Singh	28-11-2021
253	11147	Sakshi Mittal	27-11-2021
254	11148	Himanshu Rai	02-12-2021
255	11149	Navneet Singh	23-11-2021
256	11151	Anupam Pathak	20-11-2021
257	11252	Govind Chaudhary	09-12-2021
258	11263	Vijay Kumar Yadav	30-01-2022
259	11152	Mohd Shadab Siddiqui	23-11-2021
260	11154	Rohit Tripathi	21-11-2021
261	11262	Prakhar Kumar	28-01-2022
262	11155	Syed Arbaaz Ali	23-11-2021
263	11156	Akanksha Tomar (Relieved w.e.f. 06-07-2022)	25-11-2021
264	11259	Ashish Kumar Singh (Relieved w.e.f. 26-07-2022)	23-01-2022
265	11157	Dinesh Kumar	23-11-2021
266	11158	Sachin Kumar Gupta	28-11-2021
267	11159	Dinesh Kumar	28-11-2021
268	11160	Niraj Yadav	24-11-2021
269	11161	Nikhil	18-11-2021
270	11162	Saurabh Gupta	03-12-2021
271	11260	Nishant Gupta	25-01-2022
272	11163	Pankaj Kumar	26-11-2021
273	11164	Bhoopendra Kumar Patel	21-11-2021
274	11165	Vipan Kumar Tripathi	28-11-2021
275	11166	Pramod Kumar	23-11-2021
276	11167	Gautam Patel	20-11-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
277	11168	Virendra Kumar Yadava	26-11,2021
278	11169	Sudhir Kumar Gupta	24-11-2021
279	11253	Ravindra Singh	10-12-2021
280	11170	Megha Pandey, Lko.	19-11-2021
281	11171	Anupriya Kaushik	24-11-2021
282	11172	Rishabh Kushwaha	26-11-2021
283	11173	Jaya Tripathi	20-11-2021
284	11174	Shivani Srivastava	21-11-2021
285	11175	Shailesh Kumar	21-11-2021
286	11176	Vaishali Dwivedi	17-11-2021
287	11177	Mansha Kushwaha	23-11-2021
288	11178	Sandeep Yadav	23-11-2021
289	11180	Vinit Kumar	21-11-2021
290	11254	Mahendra Pal	05-12,2021
291	11181	Saurav Chauhan	01-12-2021
292	11182	Brijesh Kumar Bhartiya	18-11-2021
293	11183	Poonam Singh	18-11-2021
294	11184	Pawan Kumar Yadav	24-11-2021
295	11185	Sushil Kumar Yadav	23-11-2021
296	11186	Akash Kumar	19-11-2021
297	11187	Monu Giri	21-11-2021
298	11188	Sana Aizaz	24-11-2021
299	11189	Umang Jaiswal	25-11-2021
300	11191	Anjali Yadav	23-11-2021
301	11192	Kaushal Kishor	25-11-2021
302	11193	Kamlesh Kumar	24-11-2021
303	11194	Rohan Gupta	23-11-2021
304	11256	Raghavendra Singh	14-12-2021
305	11195	Shaily Srivastava	20-11-2021
306	11197	Shikha Sharma	24-11-2021
307	11198	Pankaj Kumar Patel	19-11-2021
308	11199	Mohammad Shadab	20-11-2021
309	11200	Shivani Katiyar	23-11-2021
310	11201	Deepshikha Gautam	18-11-2021
311	11202	Amit Kumar	18-11-2021
312	11203	Shubham Pal	27-11-2021
313	11204	Anuj Kumar	01-12-2021
314	11205	Anees Kumar Patel	19-11-2021
315	11206	Vaishali Chaudhary	23-11-2021

1	2	3	4
		(S/Sri)–	
316	11207	Himani Mudgal	02-12-2021
317	11257	Shrestha Rao	05-12-2021
318	11208	Rahul Kumar	25-11-2021
319	11209	Manish Kumar Singh	20-11-2021
320	11210	Monika Pandey	02-12-2021
321	11211	Ankum Singhal	27-11-2021
322	11212	Abhisek Bhaskar	23-11-2021
323	11213	Richa Singh	17-11-2021
324	11214	Shailendra Ramsurat Mishra	26-11-2021
325	11215	Sunil Kumar	23-11-2021
326	11216	Sunidhi Singh	23-11-2021
327	11217	Amrish Kumar Rao	20-11-2021
328	11218	Dhruv Narayan Gour	23-11-2021
329	11219	Ramesh Kumar	23-11-2021
330	11220	Vinay Kumar Patel	18-11-2021
331	11221	Ayush Gond	26-11-2021
332	11222	Ravi Shankar	23-11-2021
333	11223	Kumar Ravindra	26-11-2021
334	11224	Atul Kumar	26-11-2021
335	11225	Himanshu	20-11-2021
336	11226	Kavita Taumar	26-11-2021
337	11227	Deeksha Gautam (Relieved w.e.f. 27-04-2022)	23-11-2021
338	11228	Vivek Kumar	21-11-2021
339	11229	Mukesh Kumar	23-11-2021
340	11230	Reeta Srivas	20-11-2021
341	11231	Vikrant Sonkar	23-11-2021
342	11258	Pankaj Kishor Mishra	17-12-2021
343	11232	Janga Bahadaur Sinhail	21-11-2021
344	11233	Amresh Tiwari	17-11-2021
345	11234	Anil Kumar Tiwari (Relieved w.e.f. 10-12-2021)	20-11-2021
346	11235	Pranav Krishna Pandey	23-11-2021
347	11236	Vinay Kumar	28-11-2021
348	11237	Dileep Singh	20-11-2021

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

January 25, 2023

No. 91–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 25-01-2023, Sri Bal Gopal Singh (Emp. No-1050), Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice, is hereby appointed on the ex-cadre post of Chief Private Secretary in the Pay Matrix of Level 13-A, as per Seventh Pay Commission in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice at Allahabad.

By order of Hon'ble the Chief Justice, ASHISH GARG, Registrar General.

February 01, 2023

- **No. 92**–From the date of taking over charge, Sri Krishna Kant Singh, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 3347), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to retirement of Sri Anal Prakash.
- **No. 93**–From the date of taking over charge, Sri Ram Milan, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No.3435), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to retirement of Sri Suresh Chandra.
- **No. 94**–From the date of taking over charge, Sri Subash Chandra Yadav, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7098), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Krishna Kant Singh.
- **No. 95**–From the date of taking over chargé, Sri Alok Kumar Rai, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7041), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Ram Milan.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Sanjeev Singh Jauhari (Emp.No.7148), A.R.-cum-B.S. Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who has been permitted to draw salary from High Court, Allahabad, shall draw salary from High Court, Lucknow Bench, Lucknow).

No. 96–From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name	
1	2	3	
1	4097	Sri Ashwani Kumar Srivastava, Lko.	

No. 97–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7131	Rajendra Prasad, Lko.
2	7112	Ramesh Chandra Yadav

No. 98–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7520	Rupesh Kumar
2	7521	Mrs. Archana Srivastava
3	7522	Sandeep Srivastava

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court)

(In view of prevailing transfer policy, Sri Ashok Kumar Srivastava (Emp. No. 4094), Deputy Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; Sri Haleem Uddin Mohd. Tariq (Emp. No. 2948), Assistant Registrar and Ms. Enab Jaffrey (Emp. No. 7371), Section Officer, both posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Rajendra Prasad (Emp. No. 7131), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar).

By order of the Hon'ble Court, ASHISH GARG Registrar General.

February 03, 2023

No. 99–From the date of taking over charge, the following Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV of High Court Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Registrar-cum-Principal Private Secretary, in the pay scale of Level-13-A (1,31,100 - 2,16,600) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
1	1046	Ghan Shyam	In the vacancy against the post of Registrar-
2	1464	Sanjeev Kumar Sachdeva	cum-Principal Private Secretary created
3	1462	Atul Kumar Srivastava	vide G. O. dated 06-01-2023.

No. 100–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III of High Court Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
1	1456	Anupam Srivastava, Lko.	In consequential vacancies of Joint
2	1465	Rakesh Singh	Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV.
3	1043	Shravana Kumar Mishra	
4	1463	Afaq Ahmad	In the vacancy against the post of Joint
5	1460	Mohd. Azad Ansari	Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV created vide G.O. dated 06-01-2023.
6	2666	Krishna Kumar Baranwal, Lko.	created via Giol anica of 51 2525.
7	2667	Anuj Krishna Srivastava, Lko.	
8	1050	Bal Gopal Singh	
9	1950	Vijai Kumar Bajpai, Lko.	
10	1054	Hari Shanker Misra	
11	1056	Ratan Prakash Dwivedi	
12	1059	Syed Akhtar Mohd. Meqdad	
13	1060	Mohd. Ishrat	

No. 101–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
1	1774	Arjun Prasad, Lko.	In consequential vacancies of Deputy
2	1544	Pramod Kumar Bajpai	Registrar-cum-Private Secretary Grade-III.
3	1563	Syed Fahim Husain	
4	1537	Syed Faheem Ahmad	
5	1558	Mohd. Umar Khan, Lko.	
6	1559	Mohd. Fahim Akhtar, Lko.	
7	1545	Mohd. Tarik	
8	1546	Kalim Uddin Siddiqui	
9	1538	Raj Kumar	
10	1554	Sushil Kumar Singh	
11	1572	Mohd. Ayyub	
12	1548	Jai Singh Patel	
13	1541	Girja Shanker Sharma	

1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
14	7140	Ravindra Kumar Singh	In the vacancy against the post of Deputy
15	1550	Lal Bahadur Maurya	Registrar-cum-Private Secretary Grade-III created vide G.O. dated 06-01-2023.
16	1561	Ganesh Prakash	created vide G.O. dated 00-01-2023.
17	1556	Km. Madhu Kumari, Lko.	
18	1565	Yashwant Kumar	
19	1553	Rakesh Kumar Patel	
20	1566	Rajesh Kumar	
21	1567	Ajit Kumar, Lko.	
22	1547	Rakesh Kumar Gautam	
23	1575	Gautam Soni	
24	1576	Surya Prakash	
25	1577	Om Prakash Mishra, Lko.	
26	1578	Vishva Nath Prasad Shukla, Lko.	
27	1579	Smt. Vibha Ratan	
28	1581	Km. Tripti Sinha	
29	1583	Sandeep Kumar	
30	3500	Awadhesh Kumar	
31	3506	Shyam Lal	
32	3501	Nand Lal Yadav	
33	6883	Naresh Pal, Lko.	
34	3502	Rakesh Kumar Maurya, Lko.	
35	3504	Mukesh Kumar	
36	3519	Vishwa Mohan Arora	
37	1592	Sanjay Puri	
38	3526	Jaideep Banerjee	
39	2926	Rakesh Mehta	
40	3508	Vinay Kumar	
41	3509	Vinod Kumar Goswami	

No. 102–From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S./Sri/Ms.)–	
1	1584	Piyush Kumar	In consequential vacancies of Assistant
2	6889	Amit Katiyar, Lko.	Registrar-cum-Private Secretary Grade-II.
3	3576	Ravi Shankar Srivastav, Lko.	

1	2	3	
		(S./Sri/Ms.)–	
4	6920	Akhileshwar Kumar, Lko.	
5	3566	Sunil Kumar Gupta	
6	3530	Sanjeev Ranjan	
7	3533	Km. Pratima Agrahari	
8	3582	Arun Kumar Srivastava	
9	6956	Shashi Shekher Pandey	
10	3584	Ram Singh, Lko.	
11	3553	Shiraz Ali	
12	6891	Salim Pravej	
13	3587	Paraz Ahmad	
14	6915	Sachin Mehrotra, Lko.	
15	3589	Dhirendra Tamang	
16	3590	Anil Kumar Shukla	
17	3591	Nipendra Singh Rathour	
18	3592	Ashish Prasad	
19	3593	Ajay Kumar	
20	3594	Anuj Pratap Singh, Lko.	
21	3560	Sazia Aquil	
22	3596	Nitendra Tiwari	
23	3588	Anand Verma	
24	3586	Amit Kumar Mishra	
25	3597	Chandra Prakash	
26	6890	Virendra Kumar Gupta, Lko.	
27	3601	Mukesh Srivastava	
28	3602	Shashi Prakash	
29	6882	Renu Agrawal, Lko.	
30	3598	Jaswant Kumar	
31	3585	Subodh Kumar Singh, Lko.	
32	3606	Gautam Kumar Sinha, Lko.	
33	3539	Manish Tripathi	
34	3608	Smt. Jyoti Rajwani, Lko.	
35	3609	Dhirendra Kumar	
36	3603	Santosh Kumar, Lko.	
37	7357	Arun Kumar Singh	
38	3611	Nitesh Kumar Tewary, Lko.	
39	3612	Km. Priyanka Kushwaha	
40	3613	Rabindra Kumar, Lko.	
41	3595	Sumaira Aquil	

1	2	3	4
		(S./Sri/Ms.)–	
42	3630	Manish Saxena, Lko.	In the vacancy against the post of Assistant
43	6912	Anand Kumar Srivastava, Lko.	Registrar-cum-Private Secretary Grade-II created vide G.O. dated 06-01-2023.
44	3617	Digamber Singh	created vide G.O. dated 00-01-2023.
45	1599	Arvind Kumar Gupta	
46	6954	Kuldeep Singh	
47	3623	Anand Pandey	
48	3605	Fahad Niyaz	
49	3616	Manish Kumar	
50	1594	Siddharth Srivastava	
51	3545	Gaurav Kulshrestha	
52	3621	Anoop Kumar Singh	
53	1598	Mrs. Pooja Seth, Lko.	
54		Post Reserved	
55	3541	Faridul Hasan	
56	3532	Shaukat Ali	
57	3580	Ankita Srivastava	
58	3618	Manish Himwan	
59	3629	Lalit Kumar Shukla	
60	3628	Rahul Dwivedi	
61	3626	Atmesh Kesari	
62	6952	Krishan Kumar, Lko.	
63	3620	Sunil Kumar Sharma	
64	3619	Sailesh Prajapati	
65	3544	Manoj Kumar Yadav	
66	3627	Dev Prakash	
67	3614	Safikurrahaman	
68	3600	Ashok Kumar	
69	3547	Raj Kumar Patel, Lko.	
70	3549	Ashok Kumar Verma, Lko.	
71	3607	Deepak Kumar Kushwaha	
72	3604	Irfan Uddin Siddiki	
73	3625	Anurag Kumar Verma	
74	3624	Anupam Singh Patel, Lko.	
75	3562	Kamlesh Kumar Maurya	
76	3622	Anil Kumar Patel	
77	3581	Anuj Nigam, Lko.	
78	3615	Imran Ahmad Siddiqui	
79	3610	Ashish Kumar Singh, Lko.	

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

February 17, 2023

No. 103–From the date of taking over charge, Sri Lalit Tripathi (Emp. No.3641), Private Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700- 2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred on account of release of one post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II kept reserved for Sri Brijesh Kumar (Emp. No. 3599), A.P.S., High Court, Allahabad.

[The above promotion shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By order of Hon'ble Court, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

February 20, 2023

No. 104—From the date of taking over, charge, following Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Registrar-cum- Principal Bench Secretary, in the pay scale of Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600):

S	l. No.	Emp. No.	Name	Remarks
	1	2	3	4
			(S/Sri/Ms.)–	
	1	3268	Babban Singh	In the vacancies against the post of Registrar-
	2	3374	Azmat Ali	cum-Principal Bench Secretary, created vide G.O. dated 19-01-2023
	3	3443	Ram Murat Maurya	0.0. dated 17 VI 2023

No. 105–From the date of taking over charge, following Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100 - 2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)—	
1	3402	Alok Kumar Verma	
2	2727	C. B. L. Srivastava, Lko.	
3	3240	Ramesh Chandra Singh	In the vecessies against the past of Joint
4	3412	Lal Chandra Kushwaha	In the vacancies against the post of Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV,
5	2717	Devendra Nath Yadav, Lko.	created vide G.O. dated 19-01-2023.
6	2758	Mukesh Kumar Srivastava, Lko.	
7	2001	Arun Kumar Srivastava, Lko.	
8	3442	Ramakant	
9	3407	Janardan Tiwari	
10	3276	Umesh Pathak	In consequential vacancies to occur due to
11	3383	Devendra Kumar Dubey promotion of Joint Registrar-c Secretary Grade-IV.	
12	3426	Dinesh Prasad Gupta	

No. 106–From the date of taking over charge, following Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
1	7125	Raj Pal.	
2	7031	Ram Autar Singh	
3	7077	Sachchidanand Singh	
4	7061	Sudhakar Tripathi	
5	7042	Dilip Kumar Pandey	
6	7145	Vijay Tripathi	In the vecencies against the next of Denuty
7	7085	Jai Prakash Gupta	In the vacancies against the post of Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III,
8	6052	Manoj Kumar Jaiswal	created vide G.O. dated 19-01-2023.
9	7050	Rais Hashim	
10	7076	Pavan Kumar Chaurasia	
11	7069	Arun Kumar Singh	
12	2741	Phool Kumar, Lko.	
13	4069	Ram Milan, Lko.	
14	2958	Manoj Kumar, Lko.	
15	7058	Jagdish Narayan Mishra	
16	7063	Syed Mohd. Mukhtar Abidi	
17	7052	Raj Kumar Kesharwani	
18	7109	Audhesh Kumar	
19	2960	Babu Lal Singh, Lko.	
20	7064	Jay Prakash Dwivedi	
21	7049	Brijesh Srivastava	
22	7093	Ram Priya Sharan Kushwaha	
23	7081	Sunil Kumar Srivastava	
24	2953	Ajeet Kumar Singh Gaur, Lko.	
25	7095	Anurag Nigam	
26	2974	Brijesh Mani Awasthi, Lko.	
27	2964	Shanti Prakash Chauhan, Lko.	

1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
28	2910	Parag Srivastava, Lko.	In consequential vacancies to occur due to
29	7054	Kuldeep Singh Negi	promotion of Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III.
30	7051	Virendra Kumar	
31	2655	Neeraj Kumar Srivastava, Lko.	
32	7057	Amit Chakravarti	
33	7083	Satish Kumar	
34	7123	Bhanu Pratap Maurya	
35	3486	Rajendra Prasad Pandey	
36	2746	Narendra Singh Kushwaha, Lko.	
37	7040	Manoj Kumar	
38	2955	Pritam Kumar Singh, Lko.	
39	2963	Haribans Chauhan, Lko.	

No. 107–From the date of taking over charge, following Bench Secretary Grade-I, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
1	2947	Ram Kishun, Lko.	In the existing vacancies of Assistant
2	2972	Jitendra Kumar, Lko.	Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II and vacancies against the post of Assistant
3	7172	Hemant Kumar Singh	Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, created vide G.O. dated 19-01-2023.
4	7014	Lovy Rezvee, Lko.	
5	2872	Sanjay Srivastava, Lko.	
6	7142	Indresh Kumar	
7	2975	Amit Kumar Bhargav, Lko.	
8	7114	Asha Ram	
9	2945	Manish Bhatnagar, Lko.	
10	2965	Khajan Singh Negi, Lko.	
11	2970	Jaswant Prasad Chaudhary, Lko.	
12	7065	Bharat	

1	2	3	4
		(S/Sri/Ms.)–	
13	7151	Dinesh Kumar	
14	7089	Santosh Dwivedi, Lko.	
15	7175	Dr. Kaushal Kishor	
16	2949	Raj Kumar Yadav, <i>Lko</i> .	
17	7115	Rajesh Kumar Srivastava	
18	2959	Umesh Chandra, Lko.	
19	2971	Ranjay Kumar Raman, Lko.	
20	7039	Subhash Chandra Shukla	
21	7129	Om Prakash Prajapati	
22	2900	Sushil Kumar Shukla, <i>Lko</i> .	
23	2954	Km. Pushpa Arya, Lko.	
24	7121	Dharmendra Kumar	

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Sanjay Kumar Dwivedi (Emp. No. 2712), J.R.-cum-B.S. Grade-IV, Sri Vinay Kumar Sharma (Emp. No. 4070), D.R.-cum-B.S. Grade-III, Sri Vijay Kumar Srivastava (Emp. No. 2659), D.R.-cum-B.S. Grade-III, Sri Sanjeev Singh Jauhari (Emp. No. 7148), A.R.-cum-B.S. Grade-II and Sri Karamjeet Singh Bedi (Emp. No. 7012), A.R.-cum-B.S. Grade-II, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Devendra Nath Yadav (Emp. No. 2717), Sri Mukesh Kumar Srivastava (Emp. No. 2758) and Sri Arun Kumar Srivastava (Emp. No. 2001), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as J.R.-cum-B.S. Grade-IV. Sri Neeraj Kumar Srivastava (Emp. No. 2655), Sri Narendra Singh Kushwaha (Emp. No. 2746), Sri Pritam Kumar Singh (Emp. No. 2955) and Sri Haribans Chauhan (Emp. No. 2963), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as D.R.-cum-B.S. Grade-III. Further, Sri Rakesh Tewari (Emp. No. 7547), Sri Piyush Kumar (Emp. No. 7434), Sri Pradeep Verma (Emp. No. 7424), Sri Himanshu Pandey (Emp. No. 7600), Sri Chandra Bhushan Singh (Emp. No. 7417), Sri Vikram Singh Chandel (Emp. No. 7418), Sri Anil Kumar Lal (Emp. No. 7382), Sri Adhir Kumar Misra (Emp. No. 7562), Sri Bhanu Pratap Rawat (Emp. No. 7642), Sri Deepak Gour (Emp. No. 7584), Sri Mohd. Shabbir (Emp. No. 7970) and Sri Shashwat Pandey (Emp. No. 7986), all Bench Secretaries Grade-I, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court.)

> By order of the Hon'ble Court, ASHISH GARG, Registrar General.

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION *February* 21, 2023

No. 108—The following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III is hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. No. Ve.Aa.-2-773/X-62/(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
1	1521	Sri Sunil Kumar Verma	15-11-2022

By order of Hon'ble Court, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION] NOTIFICATION

February 22, 2023

No. 109–In partial modification of Notification No. 89 dated 23-01-2023, the date of confirmation of Sri Chandresh Kumar Vishwakarma (Emp. No. 7361), Section Officer, be now read as 22-09-2021 in place of 16-09-2021.

By order of Hon'ble Court, ASHISH GARG, Registrar General.

February 25, 2023

No. 110–From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name	
1	2	3	
1	2962	Sri Omendra Kumar Verma, Lko.	

No. 111–From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7524	Sri Amit Kumar Shukla

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Omendra Kumar Verma (Emp. No. 2962), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar. Further, Ms. Shipra Gupta (Emp. No. 7372), Section Officer, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court).

March 01, 2023

No. 112–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600):

Sl. No.	Emp. No.	Name	
1	2	3	
1	3467	Sri Sadiq Raza	

No. 113–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3463	Ravi Bhushan
2	3397	Dharmendra Kumar Pathak
3		Post reserved
4	3439	Jitendra Kumar Gupta

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 114—From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200):

Sl. No.	Emp. No.	Name		
1	2	3		
		(S/Sri)–		
1	4091	Raj Kumar Pandey		
2	6020	Anil Kumar Srivastava		
3	6010	Kamta Nath		
4	6017	Jai Shanker Misra		

No. 115–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700):

Sl. No.	Emp. No.	Name			
1	2	3			
		(S/Sri)–			
1	7133	Pradeep Kumar Maurya			
2	7106	Hari Nandan Kumar Yadav			
3	7126	Santosh Kumar Singh			
4	7116	Nikhil Kumar Singh			

No. 116–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri/Mr.)–
1	7525	Abhishek Srivastava
2	7526	Rachna Singh, Lko.
3	7529	Yogesh Agarwal, Lko.
4	7532	Satyawan Pandey

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Mrinal Mishra (Emp. No. 3272), Registrar, Sri Kamlesh Kumar Misra (Emp. No. 3459), Joint Registrar, Sri Gopal Krishna Pandey (Emp. No. 3363), Joint Registrar, Sri Kailash Nath Kesarwani (Emp. No. 3366), Joint Registrar, Sri Surya Bali (Emp. No. 3371), Joint Registrar, Sri Mohd. Arshad (Emp. No. 6001), Deputy Registrar and Sri Ashok Kumar-V (Emp. No. 4095), Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, Sri Sadiq Raza (Emp. No. 3467), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Ravi Bhushan (Emp. No. 3463), Sri Dharmendra Kumar Pathak (Emp. No. 3397) and Sri Jitendra Kumar Gupta (Emp. No. 3439), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Kamta Nath (Emp. No. 6010) and Sri Jai Shanker Misra (Emp. No. 6017), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Ms. Rachna Singh (Emp. No. 7526) and Sri Yogesh Agarwal (Emp. No. 7529), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

No. 117–From the date of taking over charge, Sri Waseem Ahmad, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 2731), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, Level-13 in the vacancy caused due to retirement of Sri Ramakant.

No. 118—From the date of taking over charge, Sri Brijendra Kumar Srivastava, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 4076), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, Level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Waseem Ahmad.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Waseem Ahmad (Emp. No. 2731), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow shall draw salary from High Court, Allahabad as J.R.-cum-B.S. Grade-IV and Sri Neeraj Kumar Srivastava (Emp. No. 2655), D.R.-cum-B.S. Grade-III, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court.).

By order of the Hon'ble Court, ASHISH GARG Registrar General.

March 04, 2023

No. 119–Sri Vikas Verma (Emp. No. 11051), Assistant Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted to the post of Review Officer, with effect from 27-10-2020 *i.e.* the date of notification of promotion of his immediate Junior Sri Birjoo Yadav (Emp. No. 10923). His name is placed just above the name of Sri Birjoo Yadav (Emp. No. 10923), Review Officer in the Gradation List of Review Officer.

He shall be entitled to pay and allowances of Review Officer post with effect from the date when he assumes the duties on the post of Review Officer. No arrears of pay shall be payable to him for the period preceding the date of assumption of duties of the post of Review Officer.

No. 120—Sri Alok Singh (Emp. No. 11053), Assistant Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted to the post of Review Officer, with effect from 27-10-2020 *i.e.* the date of notification of promotion of his immediate Junior Sri Piyush Kumar (Emp. No. 10935). His name is placed just above the name of Sri Piyush Kumar (Emp. No. 10935), Review Officer in the Gradation List of Review Officer. He shall be entitled to pay and allowances of Review Officer post with effect from the date when he assumes the duties on the post of Review Officer. No arrears of pay shall be payable to him for the period preceding the date of assumption of duties of the post of Review Officer.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court.

By order of Hon'ble Court, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

March 26, 2023

No. 121–From the date of taking over charge, Shri Raj Kumar Kannaujia (Emp. 2940), holding the cadre post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III at High Court of Judicature at Allahabad, is hereby appointed on the ex-cadre post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary in the Pay Matrix of Level 13, as per Seventh Pay Commission in the Secretariat of Hon'ble the Chief Justice at Allahabad.

By order of Hon'ble the Chief Justice, (Sd.) ILLEGIBLE, Registrar General.

न्यायाधीश, उन्नाव।

कार्य-भार मुक्त प्रमाण-पत्र 08 फरवरी, 2021 ई0

सं0 371 / 15-I-153-19—प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08 फरवरी, 2021 से 09 मार्च, 2021 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत होने की प्रत्याशा में न्यायालय अपर सिविल जज जू0िंड0 कोर्ट सं0-05, उन्नाव का कार्यभार आज दिनांक 07 फरवरी, 2021 की अपरान्ह से मेरे द्वारा छोड़ा गया।

कार्यभार मुक्त अधिकारी

सोनम शर्मा ID No. UP 3540

सं0 312 / I-123-19—प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2021 से 23 फरवरी, 2021 तक (कुल 15 दिवस) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) लिये जाने की प्रत्याशा में न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, (परिवार न्यायालय) कोर्ट सं0-01, उन्नाव का पदभार आज दिनांक 08 फरवरी, 2021 को अपरान्ह से छोडा गया।

पदभार मुक्त अधिकारी

दिव्या भार्गव, आई०डी० यू०पी० 1575,

09 फरवरी, 2021 ई0

सं0 402 / I-43-18—प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2021 से 07 अगस्त, 2021 तक (कुल 180 दिन) मातृत्व अवकाश लिये जाने की प्रत्याशा में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-5, उन्नाव का पदभार, आज दिनांक 08 फरवरी, 2021 को अपरान्ह से छोड़ा गया।

पदभार मुक्त अधिकारी

आस्था श्रीवास्तव, आई०डी० यू०पी० 2080,

15 फरवरी, 2021 ई0

सं0 452 / I-42-18—प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2021 से 01 मार्च, 2021 तक (कुल 15 दिन) अर्जित अवकाश लिये जाने की प्रत्याशा में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-4, उन्नाव का पदभार, आज दिनांक 15 फरवरी, 2021 को पूर्वान्ह से छोड़ा गया।

पदभार मुक्त अधिकारी

सौरभ श्रीवास्तव, आई०डी० यू०पी० 2041,

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-४, उन्नाव।

24 फरवरी, 2021 ई0

सं0 30 / I-123-19—प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2021 से 23 फरवरी, 2021 तक (कुल 15 दिवस) का बाल्य देखभाल अवकाश का उपभोग करने के पश्चात आज दिनांक 24 फरवरी, 2021 को पूर्वान्ह में न्यायालय प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय का कार्यभार ग्रहण किया गया।

पदभार ग्रहण अधिकारी

दिव्या भार्गव, आई०डी० नं० यू०पी० 1575,

03 मार्च, 2021 ई0

सं0 567 / I-42-18—प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-4, उन्नाव का पद भार दिनांक 15 फरवरी, 2021 से 01 मार्च, 2021 तक अर्जित अवकाश प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति किये जाने की प्रत्याशा में अर्जित अवकाश उपभोग करने के उपरान्त आज दिनांक 02 मार्च, 2021 की पूर्वान्ह में मेरे द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0-4, उन्नाव का कार्य भार ग्रहण किया गया।

मोचक अधिकारी	सौरभ श्रीवास्तव, आई०डी० नं० यू०पी० २०४१,
	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-४, उन्नाव।

12 मार्च, 2021 ई0

सं० 651 / I-181-18—प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), एफ०टी०सी० महिलाओं के विरूद्ध अपराध, उन्नाव का पद भार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या-134/Admin (Services)/2021 दिनांक 08 मार्च, 2021 के अनुपालन में आज दिनांक 10 मार्च, 2021 की पूर्वान्ह में छोड़ा गया।

कार्य मुक्त अधिकारी	विरेश कुमार सोनकर, आई०डी०नं०-यू०पी०-3563
---------------------	--

16 मार्च, 2021 ई0

सं0 682 / I-181-18—प्रमाणित किया जाता है कि न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय हसनगंज तहसील, हसनगंज, जिला उन्नाव का पद भार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या-135/Admin (Services)/2021 दिनांक 08 मार्च, 2021 के अनुपालन में आज दिनांक 10 मार्च, 2021 की अपरान्ह में ग्रहण किया गया।

कार्यभार ग्रहणकर्ता

विरेश कुमार सोनकर, आई०डी०नं०-यू०पी०-3563

आगरा के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

25 मार्च, 2022 ई0 आदेश

सं0 1273 / डीएलआरसी0—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची–1

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा संख्या	/प्लॉट क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
1	2	3	4	5	6	7	8	जा रही है 9
1	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	मदनपुर मुस्त0	564	हेक्टेयर 1.916 में से रकबा 1.000	श्रेणी-5(3) (ड़) बंजर	वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अस्थायी

23 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 1327 / डीएलआरसी0—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची-1

<u>क्र</u> 0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व	गाटा	/प्लॉट	भूमि की	विवरण / प्रयोजन्, जिसके
सं0				ग्राम	संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	बाह	बाह	खेड़ा राठौर	880	7.133 में से रकबा	श्रेणी-6(2) आबादी	अस्थाई वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु
				41014		2.000	ઝાવાવા	कन्द्र का स्थापना हतु

सं0 1328 / डीएलआरसी0—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अन्सची-1

					3.6			
क्र0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व	गाटा	/ प्लॉट	भूमि की	विवरण / प्रयोजन, जिसके
सं0				ग्राम	संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
								जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	खेडी	740 /	26.832 में	श्रेणी-6(4)	अस्थाई वृहद्ध गो संरक्षण
				अडू	2मि0	से रकबा	ऊसर	केन्द्र की स्थापना हेतु
						1.000		

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 1333/डीएलआरसी0—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम अछनेरा देहात में नगर पालिका परिषद, अछनेरा के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि ''वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

				;	अनुसूची-			
क्र0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व	गाट	ा / प्लॉट	भूमि की	विवरण / प्रयोजन, जिसके
सं0				ग्राम	संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा
								रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	किरावली	किरावली	अछनेरा	252	2.9820 में	श्रेणी-	अस्थाई वृहद्ध गो संरक्षण
				देहात		से रकबा	5(3) (ভ়)	केन्द्र की स्थापना हेतु
						1.9820	बंजर	

सं0 1334/डीएलआरसी0—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम अछनेरा देहात में नगर पालिका परिषद, अछनेरा के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि ''वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

	^	
अन	सचा—1	

					3 4			
क्र0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व	गाटा	/प्लॉट	भूमि की	विवरण / प्रयोजन, जिसके
सं0				ग्राम	संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
								जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	किरावली	किरावली	अछनेरा	252	2.9820 में	श्रेणी-5(3)	अस्थाई वृहद्ध गो संरक्षण
				देहात		से रकबा	(ड़) बंजर	केन्द्र की स्थापना हेतु
						1.000		·

30 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 1351/डीएलआरसी0—उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016—20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं प्रभु एन0 सिंह, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व ७ में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि 'वृहद्ध गो संरक्षण केन्द्र'' की स्थापना हेतु पशु पालन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आगरा को अस्थाई रूप से निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ—

अनुसूची-1

					3.0	•		
क्र0	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व	गाटा	ा / प्लॉट	भूमि की	विवरण / प्रयोजन, जिसके
सं0				ग्राम	संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की
								जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	धनौला	690	1.9720 में	श्रेणी-6(4)	अस्थाई वृहद्ध गो संरक्षण
				कलां	मि0	से रकबा	बेहड़	केन्द्र की स्थापना हेतु
						1.000		· ·
								ਸੂਬ ਸਤਨ ਜ਼ਿੰਦ

प्रभु एन0 ।सह, जिलाधिकारी, आगरा।

पी०एस०यू०पी०—8 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई०। मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 मई, 2023 ई० (बेशाख 30, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, रायबरेली

21 अप्रैल. 2023 ई0

सं0 1179/21 ए-08/2020-21—ये उपविधियां जिला पंचायत रायबरेली के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्था, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियाँ

ऐसे प्रकरण / निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा :— 1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

3—ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास / कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मी० क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण / कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत रायबरेली को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब-सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

स-प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

द-पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

य-प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पूनर्निर्माण।

र-मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शें

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रायबरेली को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्निलखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावति रसीद प्राप्त करेगा।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा :--

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमान 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2-प्रस्तावित भवन / परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा-

अ-प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

ब-नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

स-नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

द-भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

य–भवन / परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

र—स्थल की-प्लान, ले-आउट प्लान, पलोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन स्ट्रक्चर विवरण, रेन हर्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैण्ड स्केल प्लान, वातानुकूलित प्लान्ट, सीवेज—जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

ल-नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

व—नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3—बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी), चार मन्जिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी :--

अग्निशमन प्रणाली व्यवस्था आपात सीढ़ियाँ व निकासी, अग्नि सुरक्षा, लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी, यदि :—

अ-प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न।

ब-प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हों।

स—प्रस्ताव निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

- 1-(क) एक आवास गृह में 4-5 व्यक्ति प्रतिगृह माना (Consider) गया है।
 - (ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम् 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

- (ग) लिन्टल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम् क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.70 मीटर चौड़ा होगा।
- (घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।
- (ङ) बहुमंजिला भवन में कम से कम एक सामान (Goods) / मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।
- (च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भ्-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।
- (छ) बहुमंजिले भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा, किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।
- 2—निम्नलिखित निर्माण / सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है :--
 - क—जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राइवर रूम, विद्युत् उप केन्द्र आदि।

ख-मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लान्ट

ग-ढके हुए पैदल पथ आदि।

- 3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।
 - (ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।
 - (ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।
 - (घ) रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.010 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।
 - (ङ) संयुक्त सण्डास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।
 - (च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।
 - (छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.0 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।
- 4—(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।
 - (ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगा।
 - (ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी, जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (I)

लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेत् भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे :-

	भवन एवं भू-उपयोग	्र भू-आच्छादन	 फ्लोर	भवन की	भवन की
	ζ.		एरिया	अधिकतम ऊँचाई	अधिकतम ऊँचाई
			रेशियो	(I) के अनुसार	अन्य जनपदों में
			(FAR)	जनपदों में	
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्गमीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्गमीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकान व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेण्ड्री, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
6	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होंम आदि धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	75	2.50	24	15
(i)	सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं	40	2.00	30	15
	अन्य कार्यालय भवन				
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए०टी०एम०	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक	(Set Back)
-------------	------------

			•	•		
क्र0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने	साईड	पीछे	लैण्ड स्केपिंग	खुला स्थान
	(वर्गमी0)	(Front)	(Side)	(Rear)	(Landscaping)	
	2	2	4	5		7
	2	3	4		6	7
		मीटर	मीटर	मीटर	मीटर	प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति	25
					100 वर्ग मीटर	
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थल

<u>क</u> ्र0	भवन / भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

1—तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्गमीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउण्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिससे दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2—अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेंमी0 राइजर अधिकतम 19 सेंमी0, एक फ्लाइट में अधिकतम राइजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

- 3-अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।
- 4-घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।
- 5—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धित, फर्स्ट एण्ड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धित, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी

क्र0	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी
1	2	3	4
		मीटर	मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाइन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन	3.7+(0.305m) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

- (क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RAW) की अनापितत प्रस्तुत करनी होगी।
 - (ख) जनरेटर केवल 'साइलेन्ट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।
- (ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।
- (घ) जहाँ अपेक्षित हों, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया / वायुसेना का अनापित्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (ङ) सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।
- (च) इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक वेब्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (i) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रूपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे, यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।
- (ज) शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन / स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे की स्वीकृति की दरें

उपविधि के खण्ड (च) विकसित जनपदों की सूची(I) व खण्ड (ङ) के उपभाग(क) व (ख) को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर रायबरेली में नक्शा स्वीकृति की दरें निम्नवत् हैं :—

- (क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन-
- सूची (I) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु० 50.00 प्रति वर्ग मीटर, रायबरेली जनपद में यह दर रु 25.00 प्रति वर्ग मीटर है।
- (ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन-
- सूची (I) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु० 100.00 प्रति वर्ग मीटर, रायबरेली जनपद में यह दर रु० 50.00 प्रति वर्ग मीटर है।
- (ग) (i) भूमि की प्लाटिंग-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।
 - (ii) भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी हेतु बैंक्वेट हॉल आदि।
 - (iii) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर०सी०सी० पाईप आदि।
 - (iv) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानत्रित)

उपरोक्त ग—(i) से (iv) तक, सूची (i) के अनुसार जनपदों में रु० 20.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु० 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

- (घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।
- (ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा-शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।
 - (च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।
- (छ) यदि स्वीकृती के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।
- (ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत से नक्शे की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृति नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।
- (झ) सूची (I) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु० २०.०० प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में रु० १०.०० प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।
- (ण) सूची (I) के अनुसार जनपदों बाउण्ड्रीवाल स्वीकृति की दरें रु० 10.00 प्रति वर्ग मीटर व्यय अन्य जनपदों में रु० 5.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।
 - नोट-(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

- 1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन / परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।
- 2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।
- 3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।
- 4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।
- 5—अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।
- 6—अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पचांयत को प्रस्तुत की जायेगी।
- 7—अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पचांयत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।
- 8—अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अन्तरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणन अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्याल्य जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी, अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।
- 9—जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की सम्भाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।
- 10—अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।
- 11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेगा, जिसमें आवेदक शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।
- 12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अविध के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृति नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ती के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

15—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं परातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

16-भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

17—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

18—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

19—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशिया (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

20—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

21-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

22—इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अविध के लिए वैध एवं मान्य होगी।

23—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

- (क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।
- (ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत रायबरेली से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापित्त प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमित प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत रायबरेली यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु० 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो सके कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

डा० रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

जिला पंचायत, इटावा

01 मई, 2023 ई0

सं0 1971 / 23-जि0पं0-उपविधि / 2023—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, इटावा ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) के परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी गयी हैं—

- 1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।
- 2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा सं०, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी है।
- 3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।
- 4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राईंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज / इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाईस पर बने उस नक्शे से है जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाईन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।
- 5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।
- 6—भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टॉप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Verticle) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सिम्मिलत नहीं होगी।
- 7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।
- 8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे— रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाईप भी सम्मिलित है।

- 9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।
- 10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला-फिरा जाता है।
- 11—प्लोर एरिया रेशियों (FAR) का तात्पर्य उस भाग से हैं, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।
 - 12-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।
- 13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे— पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।
- 14—ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली, जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।
 - 15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-
 - (अ) अभियन्ता-अभियन्ता जिला पंचायत, इटावा।
 - (ब) अवर अभियन्ता—इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।
 - 16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत इटावा से है।
- 17—अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रायोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।
- 18—स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।
- 19—रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी का उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।
- 20—सेट-बैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउण्ड्री दीवार के बीच छोडी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।
 - 21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, इटावा से है।
 - 22-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संगठित जिला पंचायत, इटावा से है।
 - 23-अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, इटावा से है।
- 24—बहुमंजिली भवन (Multi Storey) चार मंजिला अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।
- 25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।
- 26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी,

कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शमियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः स्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सिम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रायोजन के प्राविधान सिंहत शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं।

28—व्यवसायिक / वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएस स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सिम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन / स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सिम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पादक का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो जो ज्वलनशील या भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कांरोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वलन, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि /भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकठ्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नही है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standard यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, इटावा के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनिहतार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं / या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

1-ऐसे प्रकरण / निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नही होगा।

2—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

अ—ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतयाः निजी आवास / कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नही होगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण / कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब-सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

स-प्लास्तर व फर्श मरम्मत के लिए।

द-पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

य-प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

र-मिट्टी खोदने या मिट्टी के गड्ढे भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1-स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगाः-

ले-आउट प्लान का पैमाना : 1:500 होगा

की-प्लान का पैमाना : 1:1000 होगा

बिल्डिंग प्लान का पैमाना : 1:100 होगा

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गो का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौन आलेख।

2-प्रस्तावित भवन / परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

अ-प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

ब-नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद व पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

स-नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

य-भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

र—भवन / परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

ल—स्थल का की—प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेन्ट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लान्ट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

व-नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

स—नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3—बहु मंजिली भवन (Multy Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य व निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टयां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि—

अ-प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब-प्रस्तावित निर्माण धार्मिक की प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती है।

स—प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्त्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

- 1—(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।
 - (ख) भवन के भू-तल पर स्टिल पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तथा अनुमन्य होगी।
 - (ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।
- (घ) बेसमेन्ट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।
 - (ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम सामान (Goods) / मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।
- (च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तथा 6.0 मीटर पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर की होगी।
- (ज) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।
- 2—निम्नलिखित निर्माण / सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोडा जा सकता है।
 - (क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।
 - (ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।
 - (ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।
 - 3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।
 - (ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।
 - (ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।
 - (घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।
 - (ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।
 - (च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।
 - (छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौडाई 1.00 मीटर एवं इसे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

- 4—(क) पार्क, टोट-लोटस (Tot-Lots), लैण्ड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
 - (ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौडाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।
 - (ग) भू-कम्प रोधी व स्रक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।
- 5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।
- 6—बेसमेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे—

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		(मी0)	(मी0)
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2.	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औधोगिक भवन—	60	1.00	18	12
4.	व्यावसायिक भवन—				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्किट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एंव शैक्षणिक भवन—				
	(i) सभी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		(मी0)	(मी0)
	(ii) हायर सेकेन्डरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिंस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिग होम आदि	75	2.50	24	15
6.	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन—	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारातघर जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन–				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्पोरेट एंव अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एंव मनोरंजन काम्पलेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एंव सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए०टी०एम०	100	1.00	6	6

(छ) सेट-बैक (Set-back)

<u>क्र</u> 0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने	साईड	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग	खुला
सं0		(Front)	(Front)		(Landscape)	स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर	मीटर	प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति	25
					100 वर्ग मीटर	
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12,001-20,000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20,001-40,000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40,001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(ज) पार्किंग-स्थान

क्रमांक	भवन / भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक (ECU) प्रति 80 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक (ECU) प्रति 30 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक (ECU) प्रति 50 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, होस्टल	एक (ECU) प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक (ECU) प्रति 65 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक (ECU) प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक (ECU) प्रति 150 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का

(झ) अग्नि शमन पद्वति, अग्नि सुरक्षा एंव सर्विसिस

1—तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एंव शैक्षणिक भवन व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीपलेक्स, 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एंव अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउंड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चलाने हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2—अग्नि निकास जीने न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाई में अधिकतम राईजरों की संख्या-16 तक सीमित होगी।

3-अग्नि निकास जीने तक पहुंच दूरी 15 मीटर से अधिक नही होनी चाहिए।

4—घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचें भवनों में नही किया जायेगा।

5—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6—उपरोक्त भवन में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6) 2005 एंव राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा। जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धित, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचना और चेतावनी पद्धित, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैंन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईज़र डाउन सिस्टम आदि।

(ञ) इलेक्टिक लाईन से दरी

(9) \$(114) 11 4(1							
क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाधर दूरी	क्षैतिज दूरी				
1	2	3	4				
		मीटर	मीटर				
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा	2.4	1.2				
	सर्विस लाईन						
2	हाई वोल्टेज लाईन 33,000 वोल्टेज तक	3.7	1.8				
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक	1.8+(0.305m) प्रत्येक				
		अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर	अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर				

(ट) मोबाईल टावर्स की स्थापना

- 1—मोबाईल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) अनापित्त प्रस्तुत करनी होगी। 2—जनरेटर केवल ''साइलैंट'' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।
- 3—यदि टावर का निर्माण-भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।
- 4—जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया / वायुसेना का अनापित्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 5—सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।
- 6—इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, कम्पन (Vibration) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7—अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (I) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा करने होंगे।

8—शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन / स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाईल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ठ) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन-

जनपद में यह दर 25.00 रुपये प्रतिवर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन-

इटावा जनपद में यह दर रु० 50.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी।

- (ग) (i) भूमि की प्लाटिंग- भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।
 - (ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हॉल आदि।
 - (iii) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर०सी०सी० पाईप आदि।
 - (iv) किसी परियोजना का (Lay-out plan) तलपट मानचित्र।

उपरोक्त (ग) (i) से (iv) तक, जनपद में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

- (घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।
- (ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।
 - (च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।
- (छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।
- (ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने की, किसी भूमि पर व्यवसाय करने की, स्वीकृत नक्शे के इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन या (Lay-out plan) तलपट मानचित्र पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी।
 - (झ) इटावा जनपद में रु० १०.०० प्रतिवर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

(ण) इटावा जनपद में रु० 5.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट-(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ड) अनुज्ञा-पत्र की जारी करने की प्रक्रिया

- 1—स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन / परियोजना के नक्शें एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।
- 2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।
- 3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वंय की जायेगी।
- 4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।
- 5—अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।
- 6—अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।
- 7—अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।
- 8—अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अन्तरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अविध में यिद शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।
- 9—जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।
- 10—अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।
- 11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।
- 12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा करना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदन को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अविध के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।
- विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित

किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति की के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभय पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

- 1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमित नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमित, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।
 - 2-भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।
- 3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।
- 4—निकटतम हवाई अड्डा वाले विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियंत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो, के 5 किमीo की परिधि में 30 मीo से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।
- 5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।
- 6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिये निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।
 - 7-मल्टी लेवल पार्किंग में संरचानात्मक एवं सुरक्षा की शर्तो के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।
- 8—इन उपलब्धियों के अधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।
- 9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्ते

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

- (क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।
- (ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शें ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।
- (ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, इटावा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रू० 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

डा० राज शेखर, आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 मई, 2023 ई० (बैशाख 30, 1945 शक संवत्)

भाग ७-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख <u>23 मार्च, 2023 ई0</u> चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं० 76 / उत्तर प्रदेश-वि०स० / हरदोई / 2022 / सी०ई०एम०एस०-III-**यतः**, उत्तर प्रदेश राज्य की 154—सवायजपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं० 68 / 61—2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 154—सवायजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0—2022/पत्रा0—01/2021 के जिरये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार रामवीर, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 154—सवायजपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थीं हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टी के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए रामवीर को कारण बताओ नोटिस सं0-76 / उत्तर प्रदेश-वि०स० / 2022 / सी०ई०एम०एस०-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जिरये रामवीर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पिता श्री राम किशुन द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 89/नि०व्यय0लेखा/वि०स0सा0नि०/2022 के जिरये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रामवीर ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि रामवीर, निर्वाचन खर्ची का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 154-सवायजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी रामवीर, निवासी-ग्राम-चौसार, पोस्ट-सेमरिया, ब्लाक-साण्डी, तहसील-सवाजपुर, जिला-हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान-परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd March, 2023 02nd Chaitra, 1945 (Saka).

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 154-Sawayajpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 154-Sawayajpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Ramveer a contesting candidate of Uttar Pradesh from 154-Sawayajpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Ramveer for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Ramveer was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by Shri Ram Kishun Father of the candidate on 14th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि०स0सा0नि0 / 2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89 / नि0च्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022 dated 28th February, 2023 has reported that Ramveer has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Ramveer has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Ramveer Resident of Gram-Chausar, Post-Semariya, Block-Sandi, Tehsil-Sawayajpur, District-Hardoi a contesting candidate from 154-Sawayajpur, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख <u>23 मार्च, 2023 ई0</u> चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76 / उत्तर प्रदेश-वि०स0 / हरदोई / 2022 / सी०ई०एम०एस०-III-यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 154-सवायजपुर विधान सभा क्षेत्र का साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-68 / 61-2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जिरये की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 154-सवायजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं० 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि०स०सा०नि०-२०२२/पत्रा०-०1/२०२१ के जिरये अग्रेषित दिनांक २७ अप्रैल, २०२२ की रिपोर्ट के अनुसार लालबहादुर सिंह, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन २०२२ के निर्वाचन क्षेत्र 154-सवायजपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टी के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए लालबहादुर सिंह को कारण बताओ नोटिस सं0-76 / उत्तर प्रदेश-वि0स0 / 2022 / सी०ई०एम०एस०-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये लालबहादुर सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जिरये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लालबहादुर सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि लालबहादुर सिंह, निर्वाचन खर्ची का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि :-"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 154-सवायजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी लालबहादुर सिंह, निवासी-ग्राम-गोरिया, पोस्ट-अलीगंज ननखेरिया, जिला-हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd March, 2023
02nd Chaitra, 1945 (Saka).

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III-WHEREAS, the General Election to 154-Sawayajpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 154-Sawayajpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Lal Bahadur Singh a contesting candidate of Uttar Pradesh from 154-Sawayajpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Lal Bahadur Singh for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Lal Bahadur Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 17th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि०सा०ना० / 2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि०स्त०सा०नि० / 2022 dated 28th February, 2023 has reported that Lal Bahadur Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Lal Bahadur Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Lal Bahadur Singh Resident of Gram-Goriya, Post-Aliganj Nankheriya, District-Hardoi a contesting candidate from 154-Sawayajpur, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं० ७६ / उत्तर प्रदेश-वि०स० / हरदोई / २०२२ / सी०ई०एम०एस०—III—यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की १६०-बालामऊ (अ०जा०) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन २०२२ अधिसूचना नं०-६८ / ६१-२०२२, दिनांक २७ जनवरी, २०२२ के जिरये की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 160-बालामऊ (अ0जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं० 287 / निर्वाचन व्यय सेल / वि०स०सा०नि०-2022 / पत्रा०-01 / 2021 के जिरये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार रामकृष्ण, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 160—बालामऊ (अ०जा०) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टी के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए रामकृष्ण को कारण बताओ नोटिस सं0-76 / उत्तर प्रदेश-वि0स0 / 2022 / सी०ई०एम०एस०-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जिरये रामकृष्ण को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र-संख्या 89/नि०व्यय0लेखा/वि०स0सा0नि०/2022 के जिरये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रामकृष्ण ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि रामकृष्ण, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि :-"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 160—बालामऊ (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी रामकृष्ण, निवासी-ग्राम-भिरगहना, पोस्ट-सांक, तहसील-सण्डीला, जिला-हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd March, 2023
02nd Chaitra, 1945 (Saka).

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 160-Balamau (S.C.) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 160-Balamau (S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Ramkrishna a contesting candidate of Uttar Pradesh from 160-Balamau (S.C.) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Ramkrishna for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Ramkrishna was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 17th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89 / निव्यय०लेखा / विवस्ति / 2022 dated 28th February, 2023 has reported that Ramkrishna has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Ramkrishna has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Ramkrishna Resident of Village-Bharigahna, Post-Sank, Tehsil-Sandila, District-Hardoi a contesting candidate from 160-Balamau (S.C.), Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख <u>23 मार्च, 2023 ई0</u> चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं० 76 / उत्तर प्रदेश-वि०स० / कानपुर देहात / 2022 / सी०ई०एम०एस०—III—यतः, उत्तर प्रदेश राज्य की 208—भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं० 60 / 61—2022, दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिये जारी की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 208—भोगनीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि०स०सा०नि०—2022/पत्रा0—01/2021 के जिरये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार गोविन्द कुमार, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 208—भोगनीपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थीं हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम

(5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए गोविन्द कुमार को कारण बताओ नोटिस सं० 76 / उत्तर प्रदेश-वि०स० / 2022 / सी०ई०एम०एस०—III, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये गोविन्द कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अपने दिनांक 18 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 61/24 निर्वाचन/2022 के जिरये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी श्रीमती अंजली देवी द्वारा दिनांक 27.12.2022 को प्राप्त किया गया था ; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 61/24 निर्वाचन /2022 के जिरये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गोविन्द कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि गोविन्द कुमार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :— "यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 208—भोगनीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी गोविन्द कुमार, निवासी—महेशपुर, पोस्ट—उमरपुर, जनपद-कानपुर देहात को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

No. 76/UP-LA/Kanpur Dehat/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 208-Bhognipur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 208-Bhognipur Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Govind Kumar a contesting candidate of Uttar Pradesh from 208-Bhognipur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Govind Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 01 December, 2022, Govind Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by Smt. Anjli Devi wife of the candidate on 27-12-2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kanpur Dehat, *vide* its letter no. 61/24 निर्वाचन/2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kanpur Dehat, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 61/24 निर्वाचन/2022 dated 18th February, 2023 has reported that Govind Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Govind Kanpur has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Govind Kumar, Resident of Maheshpur, Post-Umarpur, District-Kanpur Dehat a contesting candidate from 208-Bhognipur, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं० 76 / उत्तर प्रदेश-वि०स० / कानपुर देहात / 2022 / सी०ई०एम०एस०—III—**यतः**, उत्तर प्रदेश राज्य की 207—सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं० 60 / 61—2022, दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जिरये जारी की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 207—सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि०स०सा०नि०—2022/पत्रा0—01/2021 के जिरये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महबूब, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 207—सिकन्दरा से लड़ने वाले अभ्यर्थीं हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए महबूब को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0—III, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जिरये महबूब को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अपने दिनांक 18 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 61/24 निर्वाचन/2022 के जिरये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 61/24 निर्वाचन /2022 के जिरये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महबूब ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि महबूब, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 207—सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी महबूब, निवासी—ग्राम व पोस्ट—अकारू, तहसील— डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd March, 2023
02nd Chaitra, 1945 (Saka).

ORDER

No. 76/UP-LA/Kanpur Dehat/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 207-Sikandra Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 207-Sikandra Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Mahboob a contesting candidate of Uttar Pradesh from 207-Sikandra Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 01 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Mahboob for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 01 December, 2022, Mahboob was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 26-12-2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kanpur Dehat, *vide* its letter no. 61/24-निर्वाचन/2022; and

Whereas, the District Election Officer, Kanpur Dehat, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 61/24 निर्वाचन/2022 dated 18th February, 2023 has reported that Mahboob has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Mahboob has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Mahboob, Resident of Vill. & Post- Akaroo, Tehsil-Derapur, District-Kanpur Dehat a contesting candidate from 207-Sikandra, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं० ७७ / उत्तर प्रदेश-वि०स० / कानपुर देहात / २०२२ / सी०ई०एम०एस०—III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की २०८—भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन २०२२ अधिसूचना नं० ६० / ६१—२०२२, दिनांक २५ जनवरी, २०२२ के जरिये जारी की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 208—भोगनीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि०स०सा०नि0—2022/पत्रा0—01/2021 के जिरये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार रणधीर, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 208—भोगनीपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं: और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए रणधीर को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0—III, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जिरये रणधीर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अपने दिनांक 18 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 61/24 निर्वाचन/2022 के जिरये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पुत्र श्री अजय यादव द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 61/24 निर्वाचन/2022 के जिरये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रणधीर ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरान्त उक्त विफलता के लिये न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है : और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि रणधीर, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है: और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :--

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :--

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 208—भोगनीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी रणधीर, निवासी—ग्राम व पोस्ट—भोगनीपुर, जिला-कानपुर देहात को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से, बिनोद कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग। आज्ञा से, अजय कुमार शुक्ला, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd March, 2023
02nd Chaitra, 1945 (Saka).

ORDER

No. 76/UP-LA/Kanpur Dehat/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 208-Bhognipur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 208-Bhognipur Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Randhir a contesting candidate of Uttar Pradesh from 208-Bhognipur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 01 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Randhir for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 01 December, 2022, Randhir was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by Shri Ajay Yadav son of the candidate on 27-12-2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Kanpur Dehat, *vide* its letter no. 61/24—निर्वाचन/2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kanpur Dehat, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 61/24 निर्वाचन/2022 dated 18th February, 2023 has reported that Randhir has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Randhir has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

Now Therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Randhir, Resident of Gram. & Post-Bhognipur, District-Kanpur Dehat a contesting candidate from 208-Bhognipur, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AIAY KUMAR SHUKLA

AJAY KUMAR SHUKLA,

Secretary.

पी०एस०यू०पी०–८ हिन्दी गजट–भाग ७-ख–२०२३ ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। पी०एस०यू०पी0—653 निर्वाचन—20.05.2023—125 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी0—654 निर्वाचन—20.05.2023—125 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 20 मई, 2023 ई० (बेशाख 30, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़

07 अप्रैल, 2023 ई0

सं० 51/न०पा०प०आ०/2023-24—नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ अपनी सीमा के स्थित समस्त प्रकार की आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर शासनादेश संख्या-120/सा०प्र०/2019-20—उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ के जारी शासनादेश संख्या-408/9—गौ—10—63ए—95—टी०सी० दिनांक 22 फरवरी, 2010 एवं शासनादेश संख्या-3005/नौ—9—2013—85ज /05टी०सी०, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 एवं निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश संख्या सांखियकी सेल(अ)/988/सम्पत्तिकर, दिनांक 21 मार्च 2018 के द्वारा नगरपालिका परिषद् के परिक्षेत्र में स्थित भवनों पर सम्पत्ति कर में वृद्धि/संशोधन कराने सम्बन्धी आदेशान्तर्गत पालिका द्वारा उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128, 140, 141क, 298, 299 के तहत नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ परिक्षेत्र में स्थित आवासीय/अनावासीय भवनों/भूमि पर स्वःकर मूल्यांकन व्यवस्था अर्थात् स्वःकर निर्धारण उपविधि को लागू कराने हेतु जनहित एवं पालिका हित में बोर्ड प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पालिका द्वारा स्वःकर निर्धारण उपविधि को बोर्ड स्वीकृति उपरान्त दिनांक 13 मई, 2022 को सर्वसाधारण हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया। निर्धारित अवधि में आपित्तयां न प्राप्त होने की दशा में उपविधि यथावत प्रकाशित की जाती हैं। जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

स्वःकर निर्धारण उपविधि 2022 खण्ड (क)

- 1-नाम-यह उपविधि ''स्वःकर निर्धारण उपविधि 2022 नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ कहलायेगी।
- 2—उद्देश्य—स्वःकर निर्धारण व्यवस्था के अन्तर्गत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप करके इस उपविधि में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर सम्पत्ति कर का निर्धारण कर सकेगा।
 - 3-परिभाषायं-इस उपविधि में-
 - (1) ''नगर पालिका परिषद्'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ से है।
 - (2) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

- (3) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ से है।
- (4) ''भवन/भूमि'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ की सीमा में स्थित भवन/भूमि से है।
- (5) ''स्वःकर निर्धारण प्रणाली'' से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश संख्या-408/9—नौ—10—63ए/95—टी0सी0 दिनांक 22 फरवरी, 2010 के द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है।
- (6) ''आवासीय भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रयोग भवन स्वामी / अध्यासी द्वारा आवास के रूप में किया जा रहा है।
- (7) ''अनावासीय भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग आवासीय भवन से इतर उपयोग किया जा रहा है।
 - (8) ''पक्का भवन'' से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0सी0 पद्धति से निर्मित हो।
 - (9) ''अन्य पक्का भवन'' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत सीमेन्ट / पत्थर की पटिया इत्यादि से निर्मित हो।
- (10) ''कच्चा भवन'' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, टीन शेड ऐसबेस्टस, लोहा / सीमेण्ट की चादर आदि से निर्मित हो।
- (11) ''मासिक किराया दर'' से तात्पर्य इस उपविधि में भवनों / भूमि आच्छादित क्षेत्रफल के लिये निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराया से है।
 - (12) ''वार्षिक मूल्य'' से तात्पर्य पालिका अधिनियम की धारा-140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।
- (13) ''आच्छादित क्षेत्रफल'' से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।
- (14) कार्पेट एरिया से तात्पर्य भवन के उस क्षेत्र से है जैसा उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-140 के स्पष्टीकरण—1 में वर्णित है।
- (15) "मार्ग की चौड़ाई" से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित नाली / नाला के बीच की दूरी से है। 4—क्षेत्रफल की गणना—कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

(कार्पेट क्षेत्रफल का आंगणन कुल आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत परिगणित माना जायेगा।)

इस उपविधि के गजट नोटिफिकेशन के उपरान्त वर्तमान में पालिका की आय हित में एवं उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128, 140ख व 141 के तहत पुनः पालिका क्षेत्र में स्थित आवासीय भवनों पर वार्षिक मूल्यांकन हेतु मोहल्लेवार मासिक किराया दर श्रेणी वाईज निम्नवत् होगी।

आवासीय भवनों पर स्वःकर निर्धारण हेतु मोहल्लेवार प्रस्तावित मासिक किराया दर

श्रेणी	मोहल्लों का नाम	प्रति वर्गफुट की प्रस्तावित मासिक किराया दर			सड़क की चौड़ाई	
		कच्चा भवन (टीन शेड कडियों इत्यादि छत युक्त)	पक्का भवन (साधारण फर्श युक्त)	पक्का भवन (मार्बल, टाईल्स इत्यादि फर्श युक्त)	रिक्त भू– खण्ड	
1	2	3	4	5	6	7
		रु0	रु0	रु0	रु0	
प्रथम	सिविल लाईन,	1.00	1.50	2.50	0.40	08 मी0 से कम
	आसिफगंज, कुर्मीटोला, सदावर्ती, खत्रीटोला, कटरा, सिधारी पूर्वी एवं पश्चिमी, हरबंशपुर,	1.25	2.00	3.00	0.50	08 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से कम
	मातबरगंज, पहाड़पुर, चकला, मुकेरीगंज एवं आराजीबाग।	1.50	2.70	3.50	0.70	16 मीटर से अधिक

1	2	3	4	5	6	7
		रु0	रु0	₹0	रु0	
द्वितीय	मड़या, एलवल, नरौली,	0.75	1.20	2.00	0.30	08 मी0 से कम
	पाण्डेय बाजार, बदरका, सीताराम, कोट, फराशटोला, दलसिंगार,	1.00	1.50	2.50	0.45	08 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से
	गुरूटोला, जोधी का पुरा, हीरापट्टी, बलरामपुर, कालीनगंज, रैदोपुर, बेलइसा, बाजबहादुर, नालाधर्मू एवं गुलामी का	1.25	2.00	3.00	0.55	कम 16 मीटर से अधिक
0	पूरा।					0 \
तृतीय	सर्फुद्दीनपुर, अन्नतपुरा,	0.60	1.10	1.75	0.30	08 मी0 से कम
	नीबी, पल्हेनी, मूसेपुर, करतालपुर एवं कुन्दीगढ़।	0.75	1.30	2.00	0.40	08 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से
		1.00	1.50	2.50	0.50	कम 16 मीटर से अधिक

5—अनावासीय भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति ईकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप-नियम (5) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक, कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)।	
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंगहोम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	
3	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का दो गुना।
4	छात्रावास और शौक्षिणीक संस्थान, जो अधिनियम की धारा- 177 के खण्ड (ग) के अधीन अच्छादित नहीं है।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर समान।
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का तीन गुना।
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का छः गुना।
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार की भवन।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का तीन गुना।
8	औद्योगिक इकाईयों, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का तीन गुना।
9	टावर और होर्डिंग्स वाले भवन, टी०वी० टावर दूर संचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का चार गुना।
10	अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों के उल्लिखित नहीं है।	आवासीय उपनियम (5) के अधीन वर्तमान निर्धारित दर का तीन गुना।

6—वार्षिक मूल्य की गणना विधि—आवासीय भवन का वार्षिक मूल्यांकन = कार्पेट एरिया X स्वःकर की निर्धारित मासिक किराया दर X 12

य

आच्छाादित क्षेत्रफल मासिक X स्वःकर की निर्धारित मासिक किराया दर X 12 X 80 प्रतिशत

अनावासीय भवन का वार्षिक = कवर्ड एरिया X (स्वःकर की निर्धारित मासिक किराया दर X अनावासीय भवन की मासिक किराया दर का निर्धारित गुणांक) X 12 = खुली भूमि का क्षेत्रफल X (स्वःकर की निर्धारित मासिक किराया दर X 12) मूल्यांकन = खुली भूमि का क्षेत्रफल X (स्वःकर की निर्धारित मासिक किराया दर X 12) स्वावासीय भूमि का वार्षिक = खुली भूमि का क्षेत्रफल X (स्वःकर की निर्धारित मासिक किराया दर X अनावासीय भूमि की मासिक किराया दर का निर्धारित गुणांक) X 12

- 7—वार्षिक मूल्य के आधार पर आंगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य—नगरपालिका या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय—समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करायेगा।
- (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा न करने में धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का स्वःकर निर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाये।
- (ख) नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग के भवन स्वामी / अध्यासी द्वारा दाखिल की गयी समस्त विवरणों के आंशिक भाग की अधिशासी अधिकारी यदाकदा जांच करायेगा एवं त्रुटि पाये जाने पर उपविधि में दी गयी व्यवस्थानुसार शास्ति आरोपित कर सकेगा।
- (ग) पालिका द्वारा भवन स्वामियों को निर्गत गृहकर, जलकर इत्यादि के बिल की प्राप्ति की तिथि से देय 15 दिन की अवधि में 12 प्रतिशत छूट देकर देय बिल जमा करना होगा। बिल निर्गत तिथि के 15 दिन के बाद छूट देय नहीं होगी।
- (घ) पालिका क्षेत्र में स्थित भवन स्वामी के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में यदि बिल जमा नहीं कराया जाता है तो आवासीय भवनों एवं अनावासीय भवनों की बकाया राशि पर 12 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा।
- (ड़) भवन स्वामी अपने गृहकर—जलकर का भुगतान नगरपालिका द्वारा प्रेषित बिल की आई०डी० क्रमांक पर पालिका के द्वारा संचालित भारतीय स्टैट बैंक की मुख्य शाखा रैदोपुर आजमगढ़ के खाता संख्या—35132293327 आई०एफ०एस०सी०कोड़—SBIN0000014 में आनलाईन भुगतान कर रशीद प्राप्त कर सकते हैं।
- (च) आवासीय / अनावासीय भवनों पर उक्त स्वःकर निर्धारण उपविधि के तहत वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित कर प्रत्येक भवनों की पृथक—पृथक वार्षिक मांग नियत होगी।
- (छ) स्वःकर निर्धारण का पूर्व विवरण प्रपत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में भवन स्वामी द्वारा पालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि भवन नव—निर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण प्रपत्र पालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा।
- **8—रेन्ट कन्ट्रोल के मकान**—रेन्ट कन्ट्रोल, अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने वाले आवासीय एवं अनावासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।
- 9—कर निर्धारण दर— भवन पर आंगणित वार्षिक किराया मूल्यांकन का 5 प्रतिशत गृहकर एवं 12 प्रतिशत जलकर निर्धारित होगा।
 - 10-करों में छूट (केवल आवासीय भवन की दशा में) (अनावासीय भवन की दशा में लागू नहीं)-
 - (1) स्वः ध्यासित भवनों के लिये छूट स्वः अध्यासन की अवधि की गणना उसके कर निर्धारण वर्ष उसमें उल्लिखित भवन के निर्माण वर्ष के प्रमाणित साक्ष्य के दृष्टिगत निम्न प्रकार छूट देय होगी—
 - (क) 10 वर्ष पुराने स्वः अध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
 - (ख) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
 - (ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

- (2) किराये पर उठे भवन-
- (क) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष तक पुराने होंगे का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होगा।
- (ख) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने आवासीय भवनों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगी।
- (ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनों का वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा।
- 11—कर मुक्ति—(1) भवन स्वामी / अध्यासी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासीय भवन जो 30 वर्गमीटर के भू-खण्ड पर निर्मित हो एवं उसका कार्पेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ में कोई अन्य भवन न हो, गृहकर से मुक्त होगा। अनावासीय भवन की दशा में कर मुक्ति का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- (2) ऐसे भवन गृहकर से मुक्त होंगे जिनका उल्लेख उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 129—क में सिवाय के रूप में इंगित है।
- (3) ऐसे भवन जलकर से मुक्त होंगे, जैसा की उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 129 में वर्णित है।
- (4) भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ कर अधिरोपित करेगी।
- 12—शास्ति एवं अर्थदण्ड—इन उपविधि का उल्लंघन करने एवं बिना समुचित कारण के विहित दिनांक तक विनिर्दिष्ट विवरणों को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कोई भवन स्वामी/अध्यासी भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्य छिपाने पर भवन स्वामी/अध्यासी उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 148 तथा 299 के अन्तर्गत देय होगा।
- 13—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 141ख के अनुसार वार्षिक मूल्य प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी 31 मार्च तक (अन्तिम तिथि) विहित की गयी स्वःकर विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।
 - 14—नामान्तरण आवेदन-प्रपत्र के साथ स्वःकर विवरण भरकर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 15—नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ के सीमान्तर्गत नव—निर्मित हो रही / होने वाली कालोनियों / मोहल्लों की स्वःकर दरें उसके सर्वाधिक समीप के क्षेत्र की दरों के अनुरूप प्रभावी होगी।
- **16—उपसंहार**—इस उपविधि के प्रचलन में आते ही नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ में प्रचलित कर निर्धारण प्रणाली स्वतः ही खण्डित / निरस्त मानी जायेगी।

इस प्रकार पालिका परिक्षेत्र में स्थित आवासीय एवं अनावासीय भवनों इत्यादि पर उक्त निर्धारित स्वःकर निर्धारण उपविधि, 2022 के तहत गृहकर, जलकर इत्यादि का कर निर्धारण किया जायेगा।

> मनोज कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आजमगढ।

07 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 51/न0पा0प0आ0/2023-24—नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) में दिये गये प्राविधानों के तहत कर निर्धारण सूची में अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1)(2) के खण्ड क, ख, ग, घ, ड़, च, छ में परिवर्तन/परिवर्धन हेतु उपविधि का प्रारूप तैयार कर प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया मा0 सदन की बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2022 जिसे मा0 सदन द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 02 में सर्व सम्मित से स्वीकृत किया गया हैं। मा0 सदन की स्वीकृत उपरान्त आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 13 मई, 2022 के अंक में प्रकाशन कराया गया। निर्धारित अविध में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में इस उपविधि का प्रकाशन राजकीय गजट में कराया जा रहा हैं जो गजट के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

उपविधि का प्रारूप

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147(1,2) के अनुसरण में नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ द्वारा कर निर्धारण सूची में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार उपविधि बनायी जाती है— नियम व शर्ते—

1-नाम -यह उपविधि नामान्तरण उपविधि नगरपालिका परिषद, आजमगढ 2022 के नाम से जानी जायेगी।

2—अर्थ—नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित भवन स्वामी/अध्यासी कर निर्धारण रिजस्टर हेतु स्वामित्व/अध्यासी के स्तम्भ में कर अदायगी हेतु अपने नाम परिवर्तन के लिये आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत कर उपविधि में उल्लिखित दरों के आधार पर नाम परिवर्तन करा सकेगा।

3-परिभाषा-

- " नगरपालिका" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ से है
 - (2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ अधिनियम, 1916 से हैं।
 - (3) अधिशासी अधिकारी / से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।
- 4-''भवन/भूमि'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ की सीमा में स्थित भवन/भूमि से हैं।
- 5—अचल सम्पत्ति / मकानों के हस्तान्तरण पश्चात अभिलेखों के आधार पर कर निर्धारण सूची में परिवर्तन का आधार एवं शुल्क का निर्धारण :

अधिनियम की धारा 140 से 147(2) के अन्तर्गत तैयार की गयी कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन के आधार:—

 कोई भी संशोधन पंजीकृत अभिलेखों के आधार पर ही किये जायेगें यथा रिजस्टर्ड बैनामा, रिजस्टर्ड वसीयत, रिजस्टर्ड बंटवारा, मा0 न्यायालय के आदेशों की सत्यापित छायाप्रति, भवन स्वामी की मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र, रिजस्टर्ड दान-पत्र के साथ साथ आवेदक को प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा जो निम्नानुसार है :

	•	-
1	भवन स्वामी की मृत्यु की दशा में	नाम परिवर्तन शुल्क — रु० 1,000/—
	नामांतरण शुल्क-	1 माह पश्चात विलम्ब शुल्क — रु० 500/— प्रति वर्ष की दर से
		देय होगा।
2	पंजीकृत विलेख आधारित नामांतरण	पंजीकृत विलेख के आधार पर यदि कोई सम्पत्ति क्रय की गयी है तो
	शुल्क—	उक्त सम्पत्ति पर नाम परिवर्तन शुल्क रु० 1,000 / – 1 वर्ष पश्चात्
		आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क — रु० ५०० /— प्रति माह की दर से
		देय होगा
3	पंजीकृत पारिवारिक सहमति के	नाम परिवर्तन शुल्क — रु० 1,000/—
	आधार पर नामांतरण शुल्क–	01 वर्ष पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क — रु0 500/— प्रति
		वर्ष की दर से देय होगा
4	न्यायालय के आदेश के आधार पर	नाम परिवर्तन शुल्क — रु० 1,000/—
	नामांतरण शुल्क–	1 वर्ष पश्चात आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क – रु० 500/– प्रति
		माह की दर से देय होगा
5	महन्ताई, शपथ-पत्र, उत्तराधिकार	नाम परिवर्तन शुल्क — रु० 1,000/—
	के अधार पर नामान्तरण शुल्क	1 वर्ष पश्चात् आवेदन करने पर विलम्ब शुल्क – रु० 500/– प्रति
	5	माह की दर से देय होगा
6	नामान्तरण पर विज्ञापन शुल्क के	₹0 1000/-
	मद में	

6—िकसी भी प्रकार के अपंजीकृत विलेख/दस्तावेज पर उ०प्र० शासन के कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 संख्या—क0 नि0—5—177/11—2001—500(20)/2001 के क्रम में कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही निबंधन कार्यालय में स्टाम्प शुल्क की आदायगी के पश्चात् की जायेगी।

7—नामान्तरण हेतु आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करेगा साथ ही कर निर्धारण सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र / दस्तावेज / शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

8—आवेदक द्वारा पुष्ट साक्ष्यों सिहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी / नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147(2) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचनार्थ एक माह का नोटिस एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन इस आशय से जारी करेगा कि यदि किसी को सन्दर्भित भवन स्वामी / अध्यासी के नाम परिवर्तन पर कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप से नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

9—नियत अविध के अन्दर यदि कोई आपत्ति नाम परिवर्तन हेतु नगर निगम को प्राप्त होती होती है तो नगरपालिका/या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/दस्तावेजों का गुण दोष के अधार पर परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण करेगा।

10—कर निर्धारण सूची में संशोधन हेतु जारी आपित्ति नोटिस की समयाविध समाप्त होने के पश्चात नगरपालिका / या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नाम परिवर्तन की कार्यवाही करते हुये कर निर्धारण सूची में आवश्यक संशोधन करेगा।

11—ऐसे अभिलेख और दस्तावेज जो नगरपालिका के कब्जे में हैं जिनका निरीक्षण किया जा सकेगा या जिनकी प्रतियाँ दी जा सकेगी और ऐसे प्रभार विनिर्दिष्ट करना, जो उक्त अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतियां दिये जाने हेतु उद्ग्रहणीय होगे, और निरीक्षण करने और प्रतियां दिये जाने को विनियमित किया जायेगा।

मनोज कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आजमगढ।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स तुलसी कासेल, चाइना बाजार रोड़, जिला–लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है यह कि फर्म की साझेदारी में पांच साझेदार श्री एस0 के0 तुलसी, श्रीमती सरोज तुलसी, श्री अजय तुलसी एण्ड सन्स (एच0यू0एफ0), श्रीमती रितू तुलसी, श्री अंकित तुलसी साझेदार थे। जिसमें दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को फर्म के प्रथम साझेदार श्री सुदर्शन कुमार तुलसी (एस0 के0 तुलसी) के निधन होने तथा फर्म में दो साझेदार क्रमशः श्री अजय तुलसी एण्ड सन्स (एच0यू०एफ०) एवं श्री अंकित तुलसी के दिनांक 31 मार्च, 2023 को फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से निकल रहे है, तथा इसी दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को फर्म की साझेदारी में एक साझेदार श्री अजय तुलसी नये साझेदार के रूप में फर्म में शामिल हो रहे है। वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार श्रीमती सरोज तुलसी, श्रीमती रित् तुलसी, श्री अजय तुलसी साझेदार है जिसकी सूचना दी जा रही है।

> श्रीमती सरोज तुलसी, साझेदार, मेसर्स तुलसी कासेल, चाहना बाजार रोड़, जिला–लखनऊ।

सूचना

फर्म मेसर्स द यूनाइटेड ट्रेण्डर्स 5/444 गूलर रोड आदर्श कोल डिपोट के सामने, अलीगढ़—202001 पत्रावली संख्या एएलआई—13319 में दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को पवन भाटिया के मृत्यु उपरान्त उनके उत्तराधिकारी पुत्र हिमांशू भाटिया पुत्र स्व० पवन भाटिया निवासी—जी—101 पर्ल गेटवे टॉवर से—44 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार हिमांशू भाटिया एवं प्रियांशू भाटिया है।

> प्रियांशू भाटिया, साझेदार, मेसर्स द यूनाइटेड ट्रेण्डर्स, 5/444 गूलर रोड आदर्श कोल डिपोट के सामने, अलीगढ़—202001

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स प्रयाग कन्सट्रक्शन ग्रुप, म0 नं0—225, संत कॉलोनी, कैमार वन, वृन्दावन, जिला मथुरा की पूर्व भागीदार श्रीमती प्रीती सिंह पुत्री श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह पत्नी श्री अनुज कुमार सिंह, निवासी—एम0आई0जी0—4, मम्फोर्डगंज, प्रयागराज—211002 उ०प्र० दिनांक 15 जून, 2022 से उक्त फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गई हैं। अब फर्म में श्री सुभाष चन्द कुमार व आकांक्षा द्विवेदी ही भागीदार रह गये हैं।

सुभाष चन्द कुमार, भागीदार, मेसर्स प्रयाग कन्सट्रक्शन ग्रुप, म0 नं0—225, संत कॉलोनी, कैमार वन, वृन्दावन, जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा P.P.O. No. S/41927/2013 दिनांक 19 अगस्त, 2013 में गलत नाम JAYPRAKSH PANDEY छप गया है। जो

कि सही नाम JAY PRAKASH PANDEY है। अर्थात् दो साझेदार श्री सुभाष चन्द्र जैन एवं श्री शुभम जैन है। मुझे JAY PRAKASH PANDEY के नाम से जाना और पहचाना जाये। JAY PRAKASH PANDEY S/o Shri Kripa Shankar Pandey 2G/3H/2J Radhakuni O.P.S. Nagar Kalindipuram, Prayagraj, Pradesh.

Jay Prakash Pandey.

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स तुलसी थियेटर, 12, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, जिला-लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है यह कि फर्म की साझेदारी में पांच साझेदार श्री सुदर्शन कुमार तुलसी, श्रीमती सरोज तुलसी, श्री अजय तुलसी, श्रीमती रितू तुलसी, श्री अंकित तुलसी साझेदार थे, जिसमें दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को फर्म के प्रथम साझेदार श्री सुदर्शन कुमार तुलसी का निधन होने तथा फर्म में एक साझेदार श्री अजय तुलसी पुत्र श्री सुदर्शन कुमार तुलसी के दिनांक 31 मार्च, 2023 को फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से निकल रहे है, वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार श्रीमती सरोज तुलसी, श्रीमती रितू तुलसी, श्री अंकित तुलसी साझेदार है जिसकी सूचना दी जा रही है।

श्रीमती सरोज तुलसी, साझेदार, मेसर्स तुलसी थियेटर, 12, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, जिला–लखनऊ।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स विकास ट्रेडर्स, ४४८ / ५१२ / ९, हवेलिया कालोनी, ब्रान्च रोड, डालीगंज, जिला–लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें अभी तक तीन साझेदार श्री सुभाष चन्द जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मन्जू रानी जैन थे, जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से एक नये साझेदार श्री शुभम जैन फर्म में नये शामिल हो रहे है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से फर्म के पुराने दो साझेदार क्रमशः श्री विनय जैन एवं श्रीमती मन्जू रानी जैन फर्म की साझेदारी से आपसी सहमति से स्वेच्छा पूर्वक फर्म से निकल रहे है एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से फर्म का पता परिवर्तित होकर 488 / 101, कुतुबपुर, इरादतनगर, सीतापुर ब्रान्च रोड़, डालीगंज, जिला–लखनऊ हो गया है, वर्तमान में फर्म में

जिसकी सूचना दी जा रही है।

सुभाष चन्द्र जैन, साझेदार, मेसर्स विकास ट्रेडर्स, जिला–लखनऊ।

सूचना

में, आशीष कुमार चौरसिया अधिकृत साझेदार मेसर्स पशुपति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज की हैसियत से यह सूचना देता हूं कि पंजीकृत फर्म का मुख्य स्थल पूर्व में C-32-विद्यापीट. रामसिंह राणानगर (उत्तर प्रदेश) था जो दिनांक ०१ अप्रैल, २०१९ से दोनों साझेदारों की आपसी सहमति से ग्राम मकरा (त्रिलोचन महादेव) पो0 लहंगपुर, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। फर्म का कारोबार यहीं से संचालित होगा।

> आशीष कुमार चौरसिया, साझेदार. पशुपति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बी-मोहनपूरी, मेसर्स एन्टरप्राईजेज, 31 मेरट–250002, उ0प्र0 पंजीकरण संख्या MEE/0003507 की सप्लीमेन्टरी पार्टनरशिप डीड दिनांक 12 मार्च, 2023 के अनुसार सभी साझेदारों की आपसी सहमती से फर्म साझेदारी में श्री नरेश कुमार तोमर को सम्मलित किया गया है। फर्म में वर्तमान साझेदार 1–श्री प्रमोद कुमार, 2—श्री शिवकुमार, 3—श्री नरेश कुमार तोमर है।

> प्रमोद कुमार, साझेदार।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स महालक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस वसोमा, जिला बदायूं, उ०प्र० पिनकोड–243639 (पंजीकरण संख्या B-10097) फर्म में 4 साझेदार-हरिओम शर्मा, अजूं, श्रीमती नीतू, श्रीमती मीता थे, दिनांक 07 मई, 2021 को फर्म में एक नया साझेदार अमित शामिल किया, फर्म के दो साझेदार अंजू, श्रीमती मीता अपनी स्वेच्छा से दिनांक 07 मई, 2021 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। एक साझेदार हरिओम शर्मा की मृत्यु होने के कारण उनकी साझेदारी दिनांक 07 मई, 2021 को

समाप्त हो गई। अवकाश ग्रहण साझेदारों एवं मृतक साझेदार का सारा हिसाब—िकताब चुकता हो गया है, साझेदारों या फर्म का कोई लेन—देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 2 साझेदार अमित, श्रीमती नीतू हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गई है।

अमित, साझेदार, मेसर्स महालक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आई फैक्ट्री, बदायूं, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स खेतान मिल्टरपेसियालिटी एण्ड मेडिकल रिसर्च सेण्टर आर0/ओ0 विकास नगर, सनौली रोड, बदगदवॉ, गोरखपुर, उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 24 जून, 2019 से श्री चन्द्र प्रकाश खेतान, डा० आरती अय्यर, श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं० GOR/0005040 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक

31 मार्च, 2021 से डॉ० आरती अय्यर एवं श्री मनोज कुमार अग्रवाल अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये है तथा डॉ० दीपक खेतान एवं श्रीमती निधि खेतान उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये है अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री चन्द्र प्रकाश खेतान व डॉ० दीपक खेतान एवं श्रीमती निधि खेतान जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

> चन्द्र प्रकाश खेतान, साझेदार, मेसर्स खेतान मल्टिस्पेसियालिटी एण्ड मेडिकल रिसर्च सेण्टर, बदगदवॉ, गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम अनुराग सिंह है, जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के सह अंक प्रमाण-पत्र में मेरी माता का नाम सोनी सिंह अंकित है। जो उनके घर का नाम है।

> दीपांकुर सिंह पुत्र आनन्द कुमार सिंह, नि0 380, मोहल्ला मालवीय नगर, जनपद—गोण्डा, पिन कोड—271001